ISSN-0971-8397

वसुधैव कुटुम्बकम

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना

दिसम्बर 2023 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

वर्ष का लेखा-जोखा

विशेष साक्षात्कार

आर माधवन

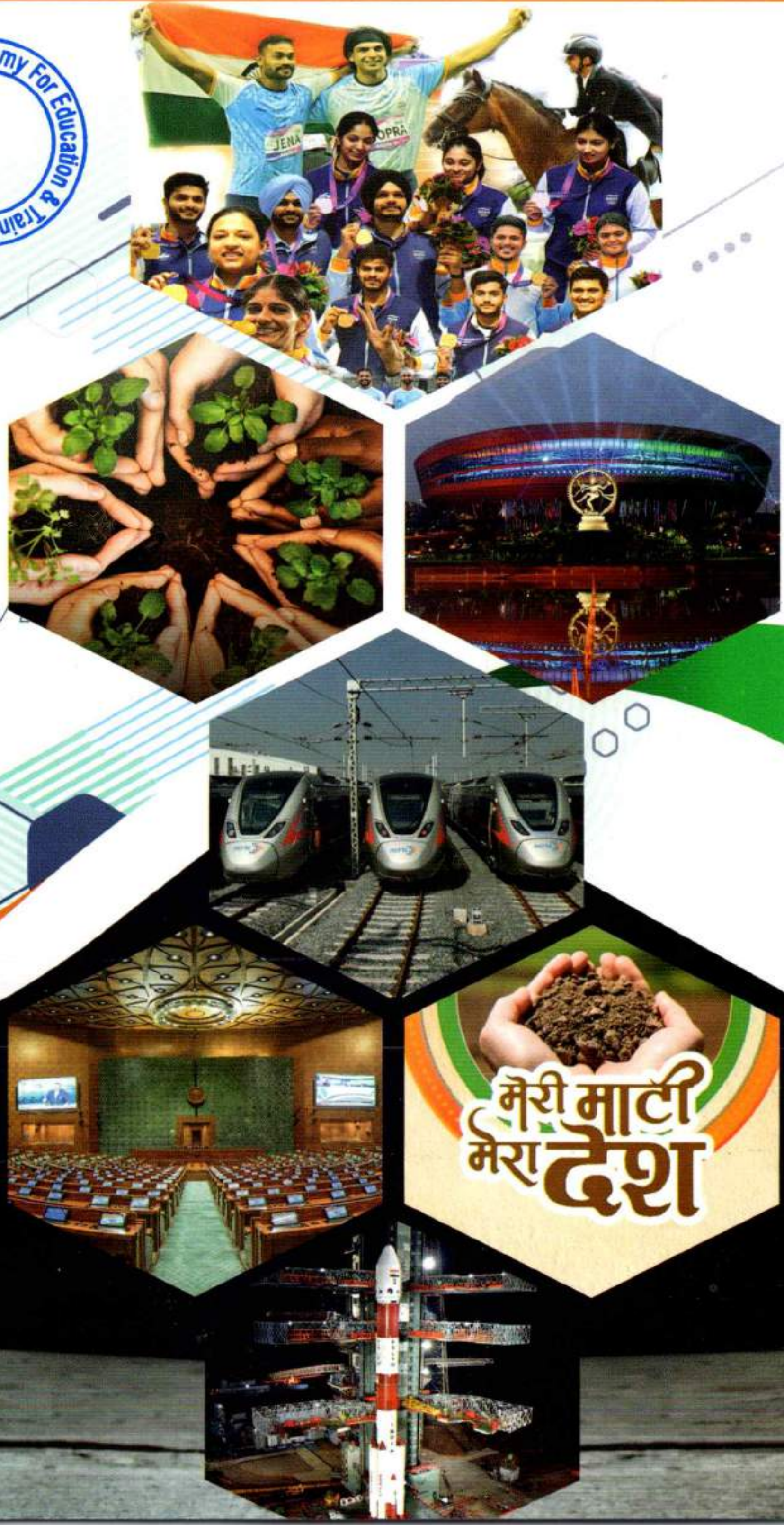

ELITE IAS
(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US
8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION www.eliteias.in

ELITE IAS

(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

Offline & Online Hindi Medium Fees Structure

MODE	BATCH DURATION	FEES (EXCLUSIVE OF GST)
Offline/Classroom	One Year Integrated Course (हिंदी माध्यम)	Rs. 29,000/-
Online/Live Classes	One Year Integrated Course (हिंदी माध्यम)	Rs. 14,000/-

Offline & Online English Medium Fees Structure

MODE	BATCH DURATION	FEES (EXCLUSIVE OF GST)
Offline/Classroom	ONE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.75,000/-
Online/Live Classes	ONE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.31,000/-
Offline/Classroom	TWO YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.1,15,000/-
Online/Live Classes	TWO YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.55,000/-
Offline/Classroom	THREE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.1,90,000/-
Online/Live Classes	ONLINE THREE YEAR	Rs.1,75,000/-
Offline/Classroom	SOCIOLOGY OPTIONAL	Rs.35,000/-
Online/Live Classes	SOCIOLOGY OPTIONAL	Rs.25,000/-
Offline/Classroom	Only NCERT Offiline	Rs.20,000/-
Online/Live Classes	Only NCERT Online	Rs.15,000/-
Online	GS Recorded Course (English Medium)	Rs.15,000/-
Online	Sociology Optional Video Course	Rs.15,000/-
Online/Offline	UPSC Prelims Test Series	Rs. 999/-
Online/Offline	UPSC Mains/Essay Test Series	Rs. 9,999/-

Learn More, Pay Less

Where Excellence Meets Affordability

Call: 8410000036, 7065202020 Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
103 & 105, 1st Floor Mall Road, Kingsway Camp, GTB Nagar Delhi-110009

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

G20

Wait is over!

Rush to grab your copy

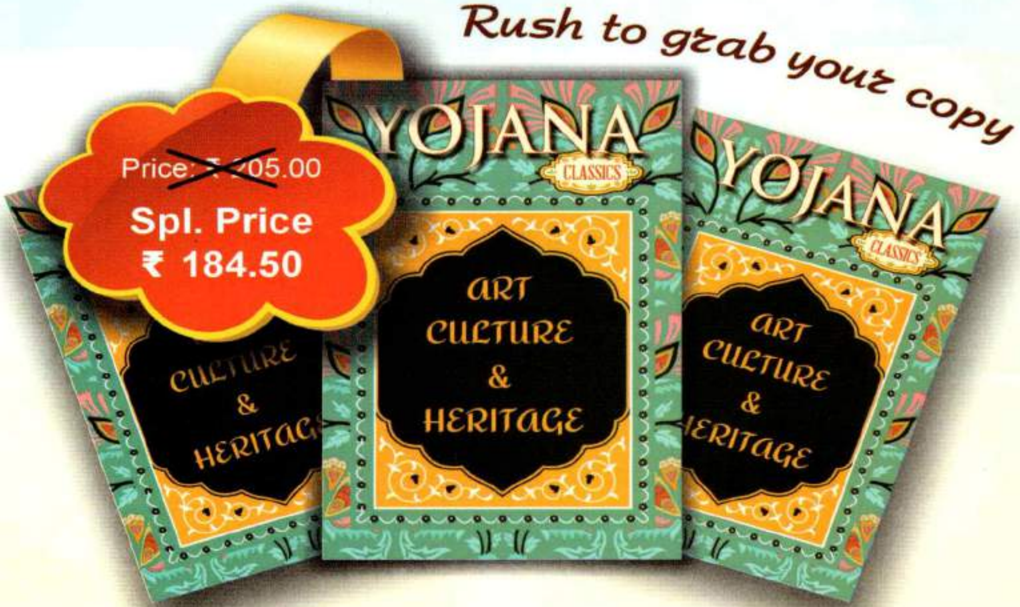

Now available

at

www.publicationsdivision.nic.in

&

Book Gallery

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003

For business related queries on this book,
contact: 011-24365609 or businesswng@gmail.com.

ISSN-0971-8397

योजना

वर्ष : 67
अंक : 12

दिसम्बर 2023
कार्तिक-अग्रहन, शक संवत् 1945

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 56

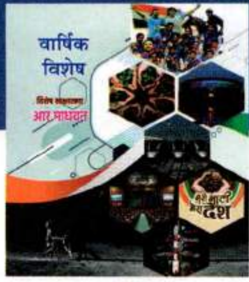

प्रधान संपादक
कुलश्रेष्ठ कमल

संपादक
डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी के सी हृदयनाथ

आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-54** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

7 अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान
सुधीर कुमार एन

11 भारत का बढ़ता रुतबा
एक उभरती हुई शक्ति
सुजन चिनॉय

25 खेल कौशल
ऐतिहासिक जीत का साल

32 आवागमन का पुनर्निर्धारण
भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव

41 भारत का उद्योग क्षेत्र

49 कृषि और ग्रामीण विकास
प्रमुख पहल और उपलब्धियां
डॉ जगदीप सक्सेना

16 आर माधवन
से विशेष साक्षात्कार
शुचिता चतुर्वेदी

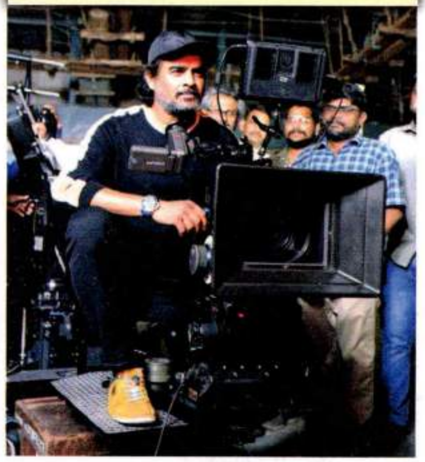

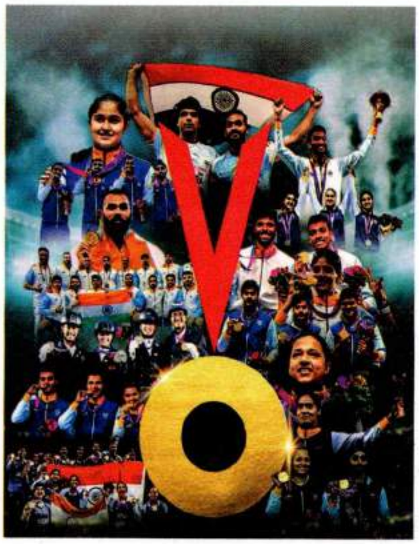

आगामी अंक : व्यवसाय करने में सुगमता
यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 38

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

अब उपलब्ध

नये कलेवर, आकार, सभी रंगीन पृष्ठों और नए स्तम्भों के साथ

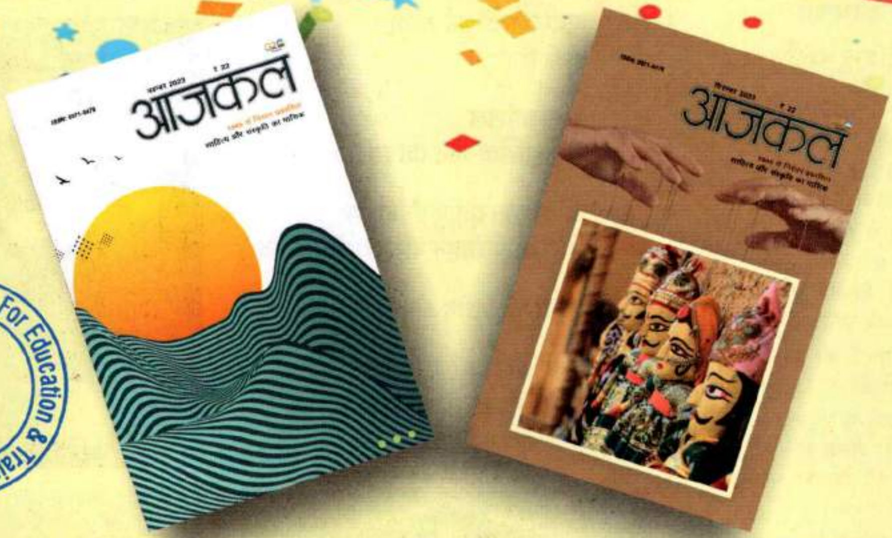

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd ★ Delhi ★

हिन्दी साहित्य विषय के प्रतियोगियों के लिए उपयोगी

आज ही अपनी प्रति खरीदें

सदस्यता के लिए स्कैन करें

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
वेब साइटः publicationsdivision.nic.in

संपादकीय

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

2023 एक नज़र में

2023 दुनिया के लिए एक उथल-पुथल भरा और असीम चुनौतियों वाला वर्ष रहा है। इस अशांत वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत सही समय पर उठाई नीतिगत पहलों के जरिये वैश्विक आर्थिक बवंडर का सफलतापूर्वक सामना करते हुए सुदृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति के रूप में उभरा है। वैश्विक विभाजन को पाटने के लिए भारत बेहतरीन स्थिति में है। जी20 शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं की मेजबानी करना और नई दिल्ली में जी20 नेताओं की उत्प्रेरक एवं व्यापक घोषणा को अपनाना भारत के कूटनीतिक कौशल को रेखांकित करता है। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना के अनुरूप जी20 शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा-पत्र में सकारात्मक समाधान के लिए कार्रवाई बिंदुओं और निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख है। इस भूमिका ने भारत को शांति और सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग और जलवायु संबंधी कार्रवाई तक की दिशा तय करने के अवसर प्रदान किए हैं और यह कई आवश्यक वैश्विक मुद्दों के समाधान की आशा प्रदान करता है।

वर्ष 2023 विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय परिवर्तनों का साक्षी रहा। भारत की 'कर्तव्य काल' की विकास और परिवर्तन यात्रा में भी यह वर्ष वास्तव में महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्प का प्रतीक है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसके बढ़ते कौशल को दर्शाता है।

औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस) और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप अपनाये जा रहे उपायों में तेजी देखी गयी। एक ओर जहां राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति प्रक्रिया सरलीकरण, नियामक ढांचे को अपनाने, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को मुख्यधारा में लाने और उचित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से मानव संसाधनों और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में दक्षता में सुधार की दिशा में उन्मुख है वहीं पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। परिवहन क्षेत्र में नेटवर्क के दायरे और सिस्टम आउटपुट में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया गया जिससे निर्माण में तेजी और हर मौसम में कनेक्टिविटी संभव हुई है। पीएम गतिशक्ति पहल के तहत भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, उड़ान आदि जैसी योजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और आर्थिक विकास में तेजी लाना है। भारत की पहली स्वदेश में डिजाइन और बनाई गयी सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रियों को एक आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा अनुभव प्रदान किया है।

सरकार ने ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने को प्राथमिकता देना जारी रखा जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा संभव हो सके। ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तीकरण के माध्यम से सरकार 'जीवन और जीवनयापन में परिवर्तन' की आकांक्षा रखती है। पीएम विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

अपनी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ भारत की सांस्कृतिक संपदा इसकी पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत और कलांजलि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विविध और जीवंत संस्कृति को उजागर किया गया जिसका समापन मेरी माटी मेरा देश के भव्य समारोह के साथ हुआ। इस वर्ष नए संसद भवन का उद्घाटन भी देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल है।

खेल सब को एक बराबर स्तर पर लाने वाला अन्य क्षेत्र रहा और इसने भारतीयों को जश्न मनाने के कई कारण दिए। सभी खेलों में एथलीटों ने देश का नाम रोशन किया। 2022 के एशियाई खेल हमारे देश के लिए उपलब्धियों के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सदैव स्मरण किये जायेंगे। 2018 के एशियाई खेलों की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक स्वर्ण पदक और 16 नई खेल श्रेणियों में पदकों के साथ भारत ने एशियाई खेलों में 107 पदक हासिल करके 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि हमारी बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ और खेल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास दोनों का प्रमाण है जिसके तहत सभी स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है। और साल का अंत क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ।

वर्ष भर का लेखा-जोखा देने वाले योजना के इस अंक का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के जीवंत सारतत्व को संजोना है और प्रमुख नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को उद्योग, परिवहन, संस्कृति, कृषि और खेल जैसे सॉफ्ट पावर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास और उपलब्धियों का व्यावहारिक विश्लेषण और झलक प्रदान करना है। यह अंक अपने पाठकों को गुजरे वर्ष और भावी अवसरों की झलक प्रदान करता है। ❑

अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान

यह वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अन्वेषण के लिए उल्लेखनीय रहा है। इसरो ने काफी पहले ही सेंटर, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस और कन्ट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। मून ऑर्बिटर मिशन, आदित्य एल-1 और चन्द्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों की सफलता का क्षेत्र इस अनूठी क्षमता को भी दिया जा सकता है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

सुधीर कुमार एन

क्षमता निर्माण और लोक संपर्क निदेशक, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)। ईमेल: sudheer@isro.gov.in

1960 के दशक के मध्य के उस दौर में जब विश्वभर की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष दौड़ में लगी थीं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केन्द्रित था। तभी से कार्यक्रम का विस्तार सामाजिक लाभ प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन-हाउस और भारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सामग्रियां और औद्योगिक प्रक्रियाएं विकसित की हैं। विगत 50 वर्षों में प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के डिजाइन विकसित करके उनका निर्माण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। प्रक्षेपण यान एवियोनिक्स (वैमानिकी) और उपग्रहों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा ही बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि इसमें आयात और रूपांतरण की कठिनाई बराबर बनी रहीं। इसरो ने इन अड़चनों को पार कर लिया और अब उप-प्रणालियों के निर्माण, असेम्बली तथा जांच-परख की आवश्यक टेक्नोलॉजी एवं बुनियादी सुविधाएं स्वयं विकसित कर रहा है। इस प्रकार इसरो विश्व की उन पांच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया, जिनके पास पृथ्वी के अध्ययन, संचार, नेविगेशन और ग्रह संबंधी खोजों की पूर्ण क्षमता है।

इसरो ने अपने किस्म की अनूठी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित कर ली है। वह अपने चार सक्रिय प्रक्षेपण यानों की सहायता से पृथ्वी की निचली, मझौली और ऊंची कक्षा में 500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। इसरो की असली ताकत है पीएसएलवी (ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान) जो 2टी श्रेणी के पेलोड अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में दुनियाभर के कमर्शियल उपभोक्ताओं को इसका अत्यधिक भरोसेमंद और किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराता है। इसका टर्न-अराउंड टाइम यानी परिवर्तन-समय बहुत सही है और उपभोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक कई प्रकार से सेटअप किया जा सकता है। पीएसएलवी को इसकी खूबियों की वजह से ही जबरदस्त लोकप्रियता मिली है, यह रॉकेट एक ही उड़ान में अनेक उपग्रह छोड़ सकता है। इसकी ऊपरी स्टेज वाले लिक्विड इंजन शुरू और बंद किए जा सकते हैं, यह विभिन्न भू-स्थिर कक्षाओं में कक्षाएं इंजेक्ट कर सकता है और पीएस4 कक्षा प्लेटफॉर्म पर अनुसंधान किए जा सकते हैं।

भारत में विकसित और निर्मित प्रक्षेपण यान एलवीएम3 में स्वयं को आवश्यकतानुसार एडजेस्ट करने की अद्भुत क्षमता है और इसने चन्द्रयान तथा वनवेब कमर्शियल वाहनों के प्रक्षेपण जैसे जटिल मिशनों में अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त की है। यह अपनी परीक्षण उड़ान के समय से ही अपने वर्ग का सर्वाधिक विश्वसनीय वाहन है। विश्वभर के कमर्शियल बाजारों में इसकी बहुत शानदार साख है और चार टन क्षमता वाले एलईओ तथा 6 टन क्षमता वाले जीईओ पेलोड्स के प्रक्षेपण के मामले में यह बहुत कामयाब है।

छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान बाजार की ज़रूरतें पूरी करने के उद्देश्य से इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) रिकॉर्ड समय में विकसित किया है और भारतीय उद्योग को इसरो की ओर से मांग आधारित समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत ही उपयोगी भेंट है।

इसरो ने काफी पहले ही सेंसर, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। मून आर्बिटर मिशन और चन्द्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों की सफलता का श्रेय इस अनूठी क्षमता को भी दिया जा सकता है। इन-हाउस ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता होने पर ही पृथ्वी के अध्ययन और ग्रह संबंधी खोज में इस्तेमाल होने वाले विशेष पेलोड्स की व्यापक रेंज विकसित करने में सफलता मिल पाई है।

उपग्रहों और उनके सम्बद्ध पेलोड के अनुसंधान और डिजाइन तैयार करने के लिए इसरो के समर्पित समूह हैं। एंटीना, रिफलेक्टर और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणालियों सहित विभिन्न उपग्रह प्रणालियों को लगातार सुधार करके आधुनिकतम बनाया जाता है, ताकि तकनीकी प्रगति की दृष्टि से वह वैश्विक मानकों के स्तर तक रहे और हो सके तो उससे भी ऊपर रहे।

देश में पूर्वी और दक्षिणी दोनों मार्गों पर प्रक्षेपण के लिए इसरो की अपनी ग्राउंड, (जमीन) प्रणालियां हैं। मास्टर कंट्रोल सुविधा तथा ट्रेकिंग और टेलीमीट्री सुविधा से सभी ईओ, संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक उपग्रहों पर चौबीसों घंटे निगाह रखी जाती है। इसरो अब अंतरिक्ष पारिस्थितिक जागरुकता (स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस) जैसी नये क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है, जिसमें उपग्रह, कचरे और अन्य आकाशीय पिंडों जैसी अंतरिक्ष वस्तुओं के व्यवहार और स्थिति सहित अंतरिक्ष के वातावरण की व्यापक समझ और जानकारी मिल सकेगी। इसरो इन प्रक्रियाओं को पूरा करने की बुनियादी सुविधाएं जुटाने की योजना बना रहा है।

इसरो ने हाल के वर्षों में अपने आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का बड़ा विस्तार करके अनेकानेक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन और प्रौद्योगिकी से जुड़े विकास में अहम सफलता प्राप्त की है। इनमें से कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं :

ट्रायसोनिक विंड टनल, हाई-एल्टिच्यूड टेस्ट फेसिलिटीज, सेमी-क्रायो टेस्टिंग और इंटिग्रेशन फेसिलिटीज़, गगनयान सुविधाएं

और कुछ वक्त के अंतराल पर प्रक्षेपण यान एक साथ प्रक्षेपित करने की क्षमता। भारत के दक्षिणी छोर पर एक नए प्रक्षेपण पैड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पहुंचाने की सतत् सुविधा कमर्शियल उद्योगों को प्राप्त होती रहेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर जीआईएस एप्लिकेशंस में ईओ डेटा प्रयोग करने के उद्देश्य से 1980 के दशक के शुरुआती दौर में एनएनआरएमएस की आधारशिला रखी गई थी जिसमें लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों का सहयोग लिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए ही इसरो ने आईआरएस कार्यक्रम तैयार किया जिसमें पहली पीढ़ी के उपग्रह शामिल थे। अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति भी हुई है जैसा कि कार्टोसेट, आरआईएसएटी (रडार इमेजिंग सेटेलाइट्स), रिसोर्ससेट, ओशियनसेट और कई अन्य उपग्रहों के प्रक्षेपण से स्पष्ट पता चलता है। ये उपग्रह विभिन्न उपभोक्ताओं को हाई रेज़ोल्यूशन डेटा उपलब्ध कराते हैं। इसरो निरंतर कवरेज करने की दृष्टि से बड़ी संख्या में ईओ उपग्रह बनाए रखता है। ईओ डेटा के व्यापक प्रयोग से मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,

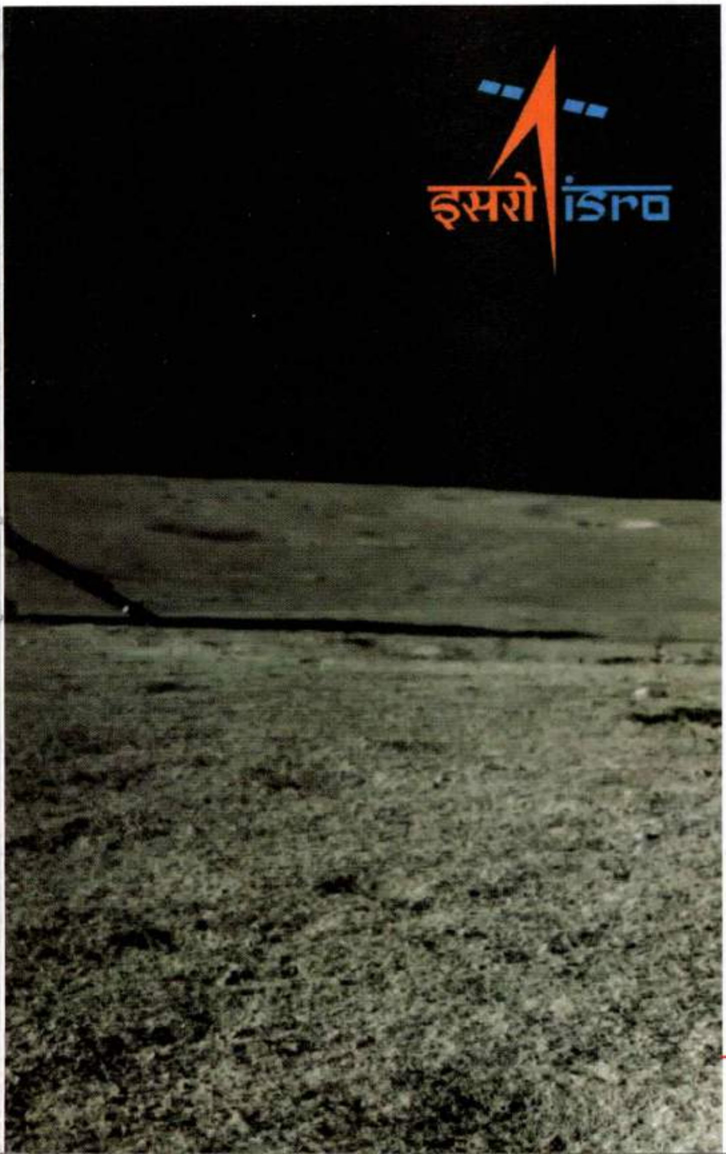

अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामित्व और यूआईडीआईए जैसी विभिन्न योजनाओं को ईओ डाटा से बहुत फायदा पहुंचा है।

उपग्रह क्षमता की जबरदस्त मांग पूरी करने के वास्ते इसरो के पास हाई-थ्रूपुट वाले और परंपरागत संचार उपग्रहों का बहुत बड़ा बेड़ा है।

अपने संचालित नाम 'नाविक' से जानी जाने वाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) भारतीय तारामंडल के नेविगेशन की भूमिका निभाती है। यह प्रणाली भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर के घेरे में भारत और इस क्षेत्र के लिए एकदम ठीक सही-समय वाली पोजिशनिंग और टाइमिंग (स्थिति और समय का आकलन) सेवाएं उपलब्ध कराती है। नाविक से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं में यान ट्रेकिंग और फ्लीट प्रबंधन, मोबाइल फोनों में उपलब्ध लोकेशन आधारित सेवाएं, यात्रियों के लिए पृथ्वी संबंधी नेविगेशन सहायता, समय विभाजन, आपदा प्रबंधन और अन्य कई सेवाएं शामिल हैं। हमारे विशेष उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं भी इस प्रणाली से मिलती हैं। आईआरएनएसएस के तीन घटक हैं : अंतरिक्ष, जमीन और उपभोक्ता। अंतरिक्ष घटक में जीईओ और जीएसओ सतहों (प्लेन्स) में सात उपग्रहों के समूह की आधार परत होती है। इस उपग्रह-समूह में अभी हाल में एनवीएस-01 उपग्रह जोड़ा गया है, जो दूसरी पीढ़ी की उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह है। एनवीएस-01 मानक 1-2 के बस स्ट्रक्चर पर आधारित है और इसका भार 2,200 किलोग्राम से ज्यादा है। इस एनवीएस-01 उपग्रह में एल-1, एल-5 और एस फ्रीक्वेंसी बैंड्स में काम करने वाले नेविगेशन पेलोड हैं। पहली पीढ़ी की उपग्रहश्रृंखला के मुकाबले दूसरी पीढ़ी की उपग्रहश्रृंखला में एल-1 नेविगेशन बैंड शामिल है और इसमें देश में ही विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी भी है। एल-1 नेविगेशन बैंड की मदद से पोजिशनिंग, असैनिक (आम आदमी) उपभोक्ताओं के लिए नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं में बड़ा सुधार आता है तथा अंतर-ध्रुवीय और अन्य जीएनएसएस सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। अहमदाबाद के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर द्वारा डिजाइन की गई और देश में ही विकसित यह अंतरिक्ष रुबिडियम परमाणु घड़ी बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का उदाहरण है जो केवल कुछेक देशों के पास ही है। उपग्रह दो सौर चक्रसमूहों से ऊर्जा प्राप्त करता है और 2.4 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करता है। एनवीएस-01 उपग्रह लगभग 12 वर्ष की मिशन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट 28 सितंबर, 2015 को लॉन्च की गई थी, 1515 किलोग्राम भार की यह वेधशाला श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी30 (एक्सल) रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई

थी। 54 देशों के करीब 2000 लोगों ने सितंबर 2022 में एस्ट्रोसेट डेटा इस्तेमाल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एस्ट्रोसेट डेटा की मदद से 275 से अधिक शैक्षिक पत्रिकाएं और 500 से अधिक जीएसएन सर्कुलर, एस्ट्रोनोमर्स टेलीग्राम और सम्मेलन से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की जा चुकी हैं।

5 नवम्बर, 2013 को मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। ग्रहों के बीच 300 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद 24 सितंबर, 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। 8 वर्ष के जीवनकाल वाले इस मिशन में कुल पांच वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए थे, जिनसे हमें मंगल ग्रह के वातावरण (वायुमंडल), बाहरी वातावरण (एक्सोस्फीयर) और उसकी सतह की खूबियां तथा अन्य बातें जानने में बहुत मदद मिली। अप्रैल, 2022 में मंगल ग्रह की कक्षा में करीब आठ वर्ष बिताने के बाद लम्बी अवधि के ग्रहण के कारण, मंगल और सौर कोरोना पर अनेक वैज्ञानिक लक्ष्य पूरे करने के बाद इस मिशन का पृथ्वी से संपर्क समाप्त हो गया।

7,200 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एमओएम डेटा तक पहुंच पाने के लिए आईएसएसडीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराया था और इन उपभोक्ताओं ने 2700 से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा डाउनलोड किए हैं। 50 से अधिक देशों में ऐसे लगभग 400 पंजीकृत उपभोक्ता हैं।

भारत का पहला अंतरिक्ष यान 'चन्द्रयान-1' 22 जुलाई, 2008 को छोड़ा गया था और उसने 100 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा की। इसमें ग्यारह हाईटेक उपकरण लगे थे। हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता का यह शानदार कारनामा था और इसने चंद्रमा के अध्ययन के भारत के प्रयासों को हमेशा के लिए नया मोड़ दे दिया। चन्द्रयान-1 के परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के प्रभाव के अध्ययन की प्रक्रिया आरंभ की जिसे चंद्रमा की एल्टिट्यूडिनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर नाम दिया गया अर्थात् इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह की संरचना और ऊंचाई का अध्ययन करना था। 'मैन इन द मून' यानी चंद्रमा पर मानव के तहत पहली बार कोई कृत्रिम वस्तु चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाई गई थी। इसी के साथ भारत का चंद्र अभियान विविधत शुरू हुआ था।

22 जुलाई, 2019 को भारत ने सफलतापूर्वक अपना फॉलोअप मिशन चंद्रयान-2 लांच किया था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर-(लैंडर) और एक रोवर भेजा गया था। असफल सॉफ्ट लैंडिंग के बावजूद आर्बिटर अभी तक सक्रिय है और डेटा भेज रहा है। ऑर्बिटर पर अपनी किस्म के पहले कई उपकरण लगे हैं, जिनमें चंद्रमा पर पहली बार सक्रिय हुआ एल-बैंड एसएआर, 12.5 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी नक्शे तैयार करने की क्षमता वाला एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और नोबल गैसों की वैश्विक एक्सोस्फीयरिक डायनामिक्स के अध्ययन के लिए एक विशेष उपकरण शामिल है। यह अध्ययन पांच वर्ष से बराबर चल रहा है।

चन्द्रयान-3 मिशन का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्टलैंडिग और रोविंग करने की क्षमताएं रखता है। चंद्रमा के लिए यह मिशन 14 जुलाई, 2023 को भेजा गया था और इसने 23 अप्रैल, 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। वहां उतरने के बाद वैज्ञानिक पेलोड चंद्रमा के 14 दिनों तक वहां रहा और आसपास के वातावरण तथा स्थितियों का अध्ययन किया। प्रारंभिक चरण-एसटीई परीक्षण से चंद्रमा की सतह की 10 सेंटीमीटर तक की गहराई वाली परत की संरचना और उसके व्यवहार की जानकारी मिली। एलआईवीएस से चंद्रमा की सतह पर सल्फर (गंधक) मौजूद होने का पता चला। फिर, आईएलएसए ने रोवर की गतिविधियों से होने वाले कंपन रिकॉर्ड किए जबकि रंभा-एलपी ने सतह के नज़दीक मौजूद प्लाज़्मा की मात्रा को मापा। इस मिशन के लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

आदित्य एल-1 मिशन पूरी तरह सौर विज्ञान पर केंद्रित भारत का पहला मिशन है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर यह अंतरिक्ष यान सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में लैगरेंज प्वाइंट एल-1 के प्रभामंडल में प्रवेश करेगा। यह उपग्रह इस प्रभामंडल में प्रवेश करके सुनिश्चित करेगा कि ग्रहण जैसी प्रक्रियाओं का सूर्य के अध्ययन के उसके लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, यह अंतरिक्ष के मौसम या परिस्थितियों पर सौर (सूर्य की) गतिविधियों का प्रभाव समझने की संभावना भी खोजेगा। सूर्य के फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और कोरोना की खोजबीन तथा अध्ययन करने के उद्देश्य से इस अंतरिक्ष याना में बाहर की तरफ सात यंत्र लगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सौर कणों और उसके चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। लैगरेंज़ प्वाइंट की विशेष उपयुक्त स्थिति से चार पेलोड सूर्य का सीधे अध्ययन करेंगे और शेष तीन पेलोड सौर कणों और सौर क्षेत्रों का वहीं से अनुसंधान करेंगे जिससे सौर गतिशीलता के अंतर-ग्रह माध्यमों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन हो पाएगा।

इसरो ने वैज्ञानिक अनुसंधान का एक्सपोसेट मिशन और नासा-इसरो सिंथेटिक अपरेंट टेम्प्रेचर राडार (एनआईएसएआर) पहल शुरू कर दी है जिसके अंतर्गत दोनों संगठन मिलकर कार्य करेंगे। इस समय इसरो मैन ऑन द मून और गगनयान सहित चंद्रमा के मिशनों की शृंखला पर तेज़ी से कार्य कर रहा है जिसका वास्तविक परिणाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा। अपेक्षाकृत कम समय में ही लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से आवश्यक टेक्नोलॉजी और हैवी लिफ्ट लांच (भारी प्रक्षेपण) वाहनों की योजना तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। ❑

भारत का बढ़ता रुतबा एक उभरती हुई शक्ति

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

पिछले नौ वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तर हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। आज, भारत एक विश्व मित्र (वैश्विक मित्र), एक विश्व गुरु (वैश्विक शिक्षक) और एक विश्व वैद्य (वैश्विक चिकित्सक) के रूप में उभरा है।

सुजन चिनॉय

एक पूर्व राजदूत और महानिदेशक, मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के लिए थिंक20 चेयर। ईमेल: dg.idsa@nic.in

ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष ने दुनिया को राजनीतिक, वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों से भर दिया है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, प्रतिस्पर्धी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत दोहरे विकल्पों से परे एक नई दिशा के लिए लालायित है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर घातक प्रहार किया। कोविड के बाद के पुनर्प्राप्ति चरण में, जिसमें वैश्विक समुदाय को एक साथ आना चाहिए था, इसके बजाय गहरे विभाजन देखे जा रहे हैं। ब्रेटन वुड्स संरचनाओं सहित बहुपक्षीय प्रणाली, परिणाम देने में विफल रही हैं। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के लिए मदद और आशा दुर्लभ है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जो भोजन, ईंधन, उर्वरक और विकासात्मक वित्त की उपलब्धता में व्यवधान की बहुआयामी चुनौती का सामना कर रही है।

यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि भारत ने जी20 के अपने नेतृत्व, अपने मूल्य-आधारित दृष्टिकोण, वैश्विक सहयोग पर बल देने और सभी के लिए शांति और प्रगति के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से शेष दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। इस वर्ष जी20 की भारत की अध्यक्षता, भारत और दुनिया भर

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

में कई विरोधियों द्वारा लगातार व्यक्त किए गए संदेह के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), व्यापक-आर्थिक स्थिरता, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढाँचा, जलवायु चुनौती, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत हरित परिवर्तन, और बहुपक्षीय संरचनाओं में सुधार जैसे प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने में एक बड़ी सफलता थी। एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में भारत की छवि, जो पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत से सामने आयी है, महामारी की चरम सीमा पर दुनिया भर के देशों को दिए गए टीकों और स्वास्थ्य देखभाल सहायता के परिणामस्वरूप और भी मजबूत हुई है।

भारतीय नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत को अब वैश्विक मंच पर पर्यवेक्षक के रूप में नहीं देखा जाता है। यह अब परिणामों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के जी20 आदर्श वाक्य और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित एक उदाहरण, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (एयू) को जी20 में शामिल करना है, जो भारत की ''किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना'' संबंधी वकालत को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण विकास, जो जी20 संरचना को अधिक प्रतिनिधिक बनाता है, वैश्विक दक्षिण के एक सच्चे मित्र के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में परिलक्षित सकारात्मक परिणाम हाल के वर्षों में मोदी सरकार द्वारा की गई कई पहलों से मेल खाते हैं। महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता कार्यक्रम के अलावा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई), और लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक है। इस सूची में ग्रीन ग्रिड पहल-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) को जोड़ा जाना चाहिए, जिसे 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की पहली असेंबली में पीएम मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

मिशन लाइफ और जलवायु संकट

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अवक्रमण दुनिया की दो सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में उभरी हैं, जिनमें भावी पीढ़ियों के लिए अकल्पनीय प्रतिकूल परिणाम पैदा करने की क्षमता है। यहीं पर भारत ने स्थिति को सुधारने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विस्फोटक व्यापारवाद जो विकसित पश्चिम और संकटग्रस्त वैश्विक दक्षिण के बीच दरार को दर्शाता है, से परे एक अलग रास्ते की ओर संकेत किया है। भारत ने एक नई नैतिक दिशा-निर्देश की पेशकश की है, जिसे पहली बार ग्लासगो में पीएम मोदी ने मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के माध्यम से समझाया था, जो व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई विमर्श को केंद्र में रखता है।

सतत विकास के लिए जीवन शैली पर जी20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों के रूप में संहिताबद्ध, अब इस मिशन का उद्देश्य स्थायी उपभोग पैटर्न के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल

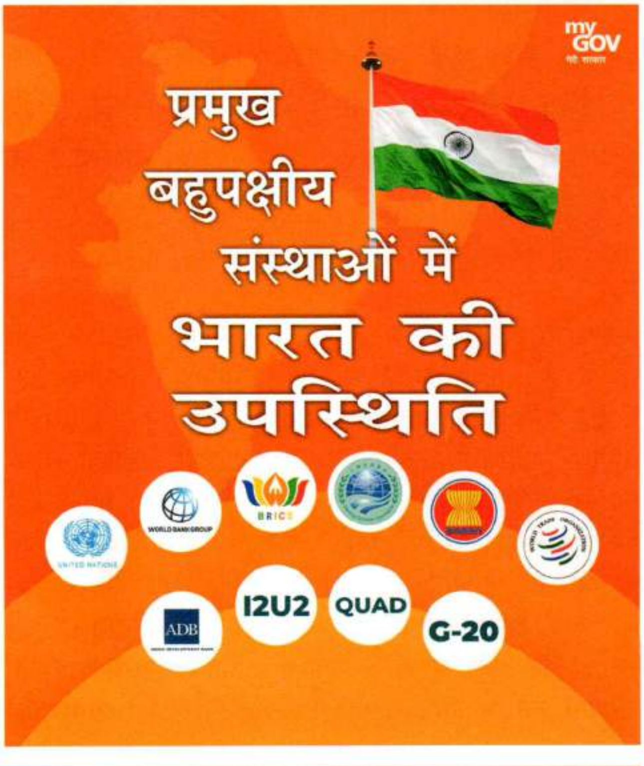

जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क का प्रचार करना है। अपनी ओर से, भारत एकमात्र जी20 देश है जिसने अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 2030 के निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लिया है। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने भी स्वीकार किया कि भारत स्वच्छ ऊर्जा में एक निर्विवाद विश्व नेता है।

पीएम मोदी ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक जलवायु शमन अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करने का वादा करता है। भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करके अपनी जलवायु कार्रवाई को तेज करने का इरादा व्यक्त किया। यह अद्यतन 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।

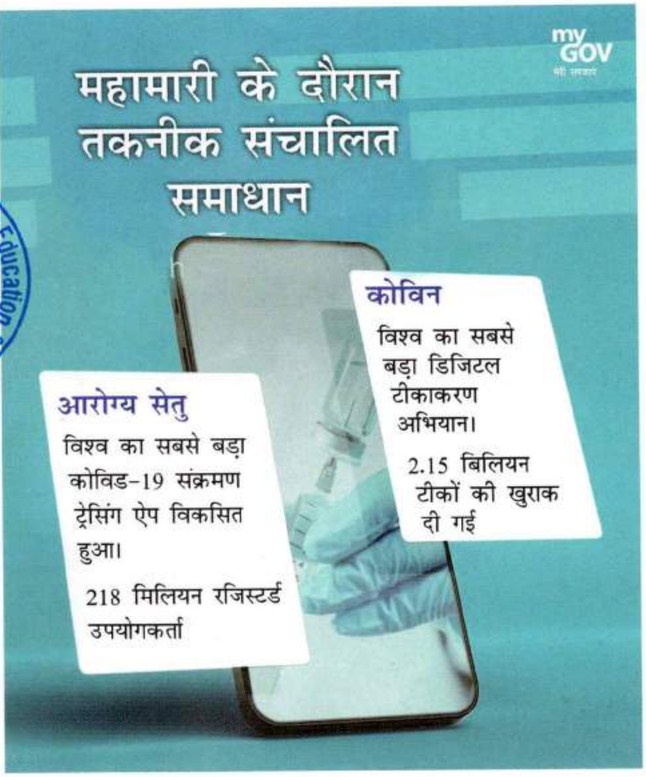

स्वच्छ ऊर्जा

इसी तरह, जून 2022 में जी-7 शिखर सम्मेलन में, पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "भारत में दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। भारत की विशाल रेलवे प्रणाली इस दशक में नेट शून्य हो जाएगी। हमने समय से नौ साल पहले गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है।" प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावों के अलावा, भारत ने यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (यूएसआईएससीईपी) को नया रूप दिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना, उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना और पांच प्रमुख स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधानों को अपनाना है:

(i) विश्वस्त तेल और गैस स्तंभ
(ii) शक्ति और ऊर्जा दक्षता स्तंभ
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ
(iv) सतत विकास स्तंभ, और
(v) उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकियाँ।

एक और पहल यूरोपीय संघ और भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (सीईसीपी) है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे जलवायु-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा, छत पर सौर पैनल और सौर पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण का एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, जैव ईंधन और इमारतों में ऊर्जा दक्षता की गतिविधियाँ शामिल हैं। अक्टूबर 2017 में ईयू-भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान में इस साझेदारी

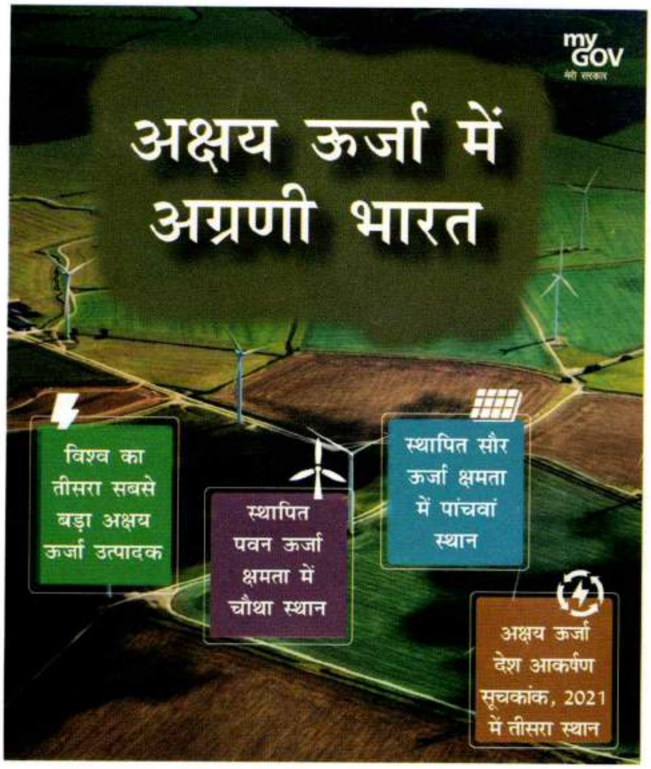

की पुन: पुष्टि की गई और बाद में जुलाई 2020 में ईयू-भारत रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की गई।

ऊर्जा पर ध्यान न केवल सामान्य प्रकृति का है बल्कि विशिष्ट भी है। भारत हाइड्रोजन में उभरते वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा और देश अक्षय शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। हरित हाइड्रोजन का निर्यात केंद्र और देश भर में विभिन्न स्थानों पर हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए, भारत ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का अनुकरण कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द ही भारत न केवल हरित हाइड्रोजन बल्कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा, ताकि चल रहे व्यवधानों के लिए सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में एक बड़ी छलांग मिलेगी।

लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ

दिसंबर 2021 में, सरकार ने भारत में चिप विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। मार्च 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र विकसित करने के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। अप्रैल 2022 में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक भागीदार के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में "एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिज़ाइन प्रतिभा पूल है, जो दुनिया के 20 प्रतिशत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियरों को बनाता है।'' इसके अलावा, शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों में से अधिकांश के डिजाइन या अनुसंधान एवं विकास केंद्र हमारे देश में हैं।

ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहयोग से शुरू की गई त्रिपक्षीय आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल, एक और आपूर्ति शृंखला संकट का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य चीन से दूर तीन देशों और समान विचारधारा वाले भागीदारों के लिए आपूर्ति शृंखला विविधीकरण का समन्वय और प्रोत्साहन करना है। नई पहल विकसित करने के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी के संबंध में संभावित एकाधिकार और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के व्यापक निहितार्थों की भी जांच जरूर करनी चाहिए, जिनमें से कई हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है। दिनांक 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री ने भारत को एक सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत की। तब से, पिछले आठ वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में भारी वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट की वहनीयता और पहुंच बढ़ाना तथा देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से शासन में पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज, लगभग सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों के सभी विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2021 में, भारत ने 48 बिलियन वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन, या वैश्विक कुल का 40 प्रतिशत दर्ज किया। दिलचस्प बात यह है कि यह चीन से लगभग तीन गुना अधिक है और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं: अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त रीयल टाइम भुगतान मात्रा से सात गुना अधिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल परिवर्तन किसी से अनदेखा नहीं रहा। दुनिया भर के देशों ने यूआईडीएआई, आधार और एकीकृत भुगतान पोर्टलों के भारतीय मॉडल में रुचि दिखाई है जो

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

भारत की विशाल आबादी को एक निर्बाध समग्रता से जोड़ते हैं।

योग और आयुर्वेद

भारत पारंपरिक रूप से वैश्विक कल्याण में योगदान देने में उत्कृष्ट रहा है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया, जब इसने लगभग 100 देशों को मुफ्त टीके प्रदान किए और अफगानिस्तान, यूक्रेन और कई अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता और मानवीय सहायता भेजी। भारत ने न केवल टीकों का निर्यात करके बल्कि स्वस्थ रहने की आदतों को बढ़ावा देकर इलाज से भी अधिक रोकथाम का समर्थन किया है। रोग और चिकित्सा की पश्चिमी धारणा पूर्वी प्रारूप से भिन्न है। भारत चिकित्सा के हिस्से के रूप में भोजन और योग जैसी पारंपरिक प्रथाओं में विश्वास करता है जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

2014 में अपने यूएनजीए भाषण में, पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखते हुए इसे बढ़ावा देने की मांग की थी। योग की महान भारतीय विरासत को दुनिया के साथ साझा करना मानव जाति के लिए मोदी का व्यक्तिगत उपहार था। आज, दुनिया भर के देश वैचारिक और धार्मिक बाधाओं से परे, भारत की प्राचीन सभ्यता द्वारा दी गई समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं में योग्यता देखते हैं। जब तक भारत ने इस तरह की अग्रणी पहल के माध्यम से अपनी विरासत को साझा करने की पेशकश नहीं की, तब तक योग का अभ्यास विदेशों में महंगे स्टूडियो में किया जाता था जो अजीब व्याख्याओं के अधीन होता था, यहां तक कि खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा भी बनाया जाता था। इस पहल ने योग के सच्चे अभ्यास को उसके शुद्धतम रूप में पुनर्जीवित किया, जिससे यह दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हुआ।

कोविड के दौरान, सरकार ने प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों या सरल घरेलू उपचार को बढ़ावा दिया। यह एलोपैथिक चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक है। भारत ने विभिन्न देशों की मदद के लिए दवाओं और अन्य उपकरणों का निर्यात किया और हिंद महासागर क्षेत्र में पहला रेसपोंडेन्ट (प्रतिवादी) बन गया। वैक्सीन मैत्री ने 101 देशों में वैक्सीन पहुंचाने में मदद की। इसके अलावा, भारत ने अन्य विकासशील देशों को कोविन और आरोग्य सेतु जैसे ओपन-सोर्स ऐप प्रदान किए हैं। सरकार ने इन्हें डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में घोषित किया, जिसका उपयोग 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए किया है।

मिलेट्स यानी श्रीअन्न या मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष

खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर, घरेलू और वैश्विक पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलेट्स की क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (प्ल्वड-2023) घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने आधिकारिक तौर पर 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। यह अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक खाद्य फसल है, जहां पारंपरिक खाद्य फसलें सीमित वर्षा और खराब मिट्टी की गुणवत्ता के कारण पनपने के लिए संघर्ष करती हैं। मिलेट्स प्रमुख अनाज फसलों की तुलना में बेहतर पोषण तत्वों का दावा करता है, जो खाद्य सुरक्षा और आहार स्वास्थ्य में योगदान देता है। वे विशेष रूप से सूखे और चरम मौसम की स्थिति के प्रति लचीले होते हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं।

मधुमेह जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और परिष्कृत आहार के प्रचलन के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, आधुनिक उपभोक्ता धीरे-धीरे गेहूं और चावल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के व्यवहार्य विकल्प के रूप में ग्लूटेन-मुक्त मिलेट्स की ओर रुख कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने इस बदलाव को तेज कर दिया, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादियों ने अपने पोषण सेवन को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए मिलेट्स को अपना लिया। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान मिलेट्स के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भारी बढ़ावा मिला। भारत में आयोजित सैकड़ों जी20 कार्यक्रमों में हजारों विदेशी और भारतीय प्रतिभागियों को मिलेट्स से बने कई व्यंजन परोसे गए। भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के थिंक20 अध्यक्ष के रूप में, लेखक को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि थिंक20 सहभागिता समूह द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में मिलेट्स को प्रमुखता से दिखाया गया है।

निष्कर्ष

पिछले नौ वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तरों को हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति होगा। यह, सभी भारतीय लोगों, विशेषकर युवाओं की ओर से इस सपने को हासिल करेगा। भारत गौरव के शिखर पर पहुंचेगा क्योंकि वह आज विविध क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने और व्यापक रूप से कल्याण करने में योगदान देने को इच्छुक है। आज, व्यापार, सैन्य या वैचारिक टकराव में उलझे कई अन्य लोगों के विपरीत, भारत एक विश्व मित्र (वैश्विक मित्र), एक विश्व गुरु (वैश्विक शिक्षक) और एक विश्व वैद्य (वैश्विक चिकित्सक) के रूप में उभरा है। ❑

(व्यक्त विचार निजी हैं)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

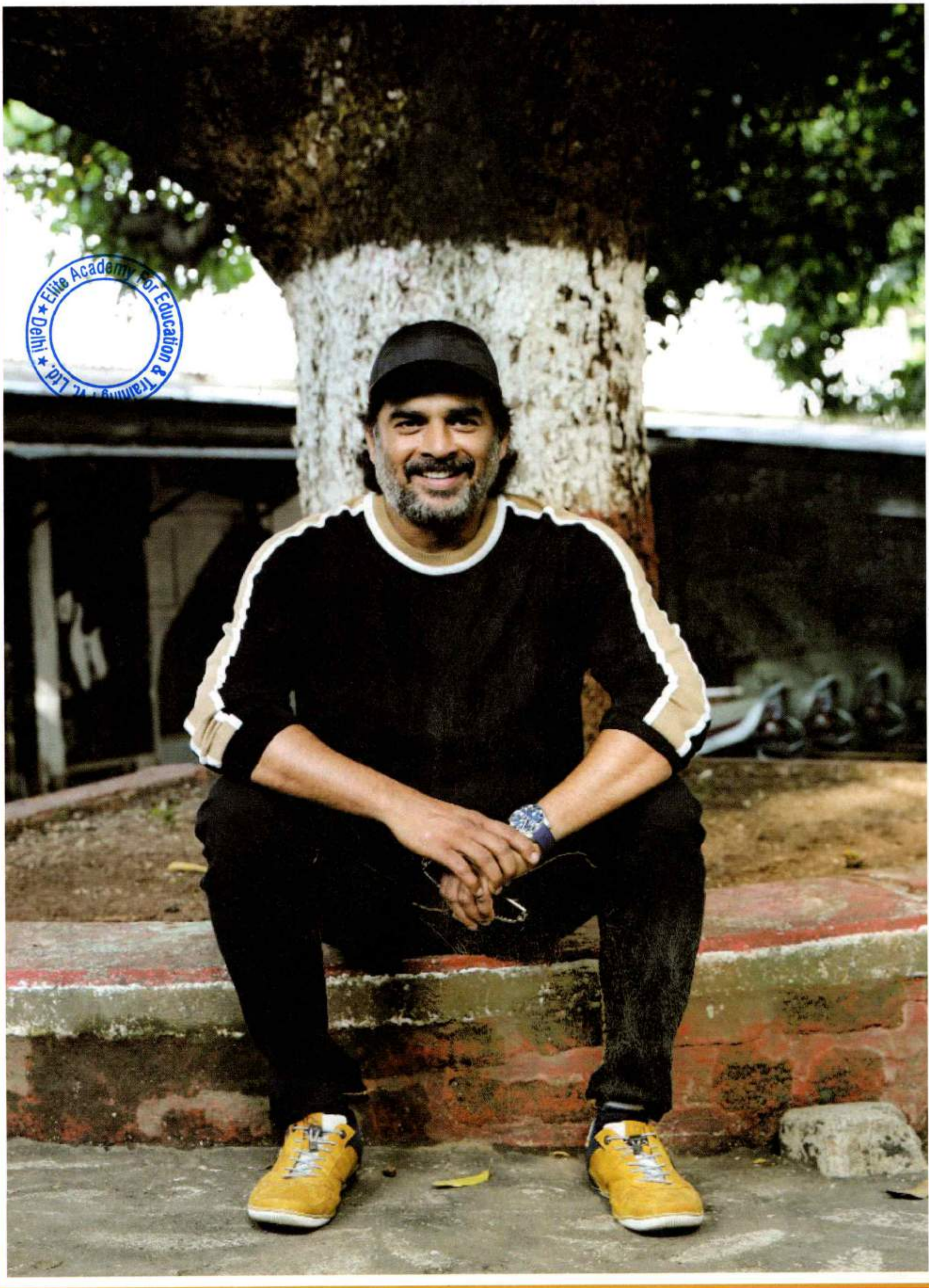
Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.
Delhi

आर माधवन से बातचीत

रंगनाथन माधवन ने अपने 30 वर्षों से अधिक के शानदार फ़िल्मी करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 1990 के दशक में शुरुआत करते हुए, माधवन ने वर्ष 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म 'अलाइपायुथे' के साथ फिल्मों में अपना पहला ब्रेक पाने से पहले, उस वक्त के उभरते हुए सैटेलाइट टीवी के साथ, धारावाहिकों के लगभग 1800 एपिसोड में काम किया। तब से, वह सिनेमा के विभिन्न रूपों, भाषाओं और शैलियों में अपनी छाप छोड़ते हुए एक अजेय शक्ति रहे हैं। माधवन एक बहुमुखी अभिनेता हैं जिन्होंने रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, गुरु और कई अन्य फिल्मों में यादगार भूमिकाएँ निभायी हैं। उन्हें हाल ही में उनके निर्देशन की पहली फिल्म 'रॉकेट्रीः द नांबी इफेक्ट' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस वर्ष, उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष की भूमिका भी संभाली है। वह एक व्यापक क्षितिज, गहराई और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो उनकी सिनेमाई उपलब्धियों की तरह ही समान रूप से प्रेरक और समृद्ध है। प्रकाशन विभाग की संपादक शुचिता चतुर्वेदी ने अभिनेता-निर्देशक और एफटीआईआई के अध्यक्ष आर माधवन के साथ दिलचस्प बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी सिनेमाई यात्रा, फिल्म-निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका, वैश्विक सिनेमा परिदृश्य, एक संबल के रूप में प्रौद्योगिकी और युवाओं के साथ उनके जुड़ाव सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंशः

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

"तकनीक आती जाती रहेगी, लेकिन कहानी कहने या प्रस्तुति की कला बनी रहेगी।"

शुचिता चतुर्वेदीः नेशनल फ़िल्म अवार्ड जीतने के लिए और एफ़टीआईआई कि इस नयी ज़िम्मेदारी की आपको बधाई। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है। आप इंजीनियर बने और साथ ही आपका डिफेंस बैकग्राउंड और उसके बाद कम्युनिकेटर, एक्टर, नेशनल अवार्ड और अब एफ़टीआईआई के अध्यक्ष। एफ़टीआईआई के लिए आपके काम और विज़न में आपका इंटेंट और मोटिवेशन कैसे दिखेगा?

आर माधवनः बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल में एक जो तारीफ़ है उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। मेरे इस एटीट्यूड में, ट्रेनिंग में, मेरी परवरिश में या मेरे कंडीशनिंग में ऐसी क्या ख़ासियत थी जो एक छोटे से शहर जमशेदपुर से निकलकर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं?

आत्मनिरीक्षण करने पर, मुझे कई ऐसे कारण मिलते हैं जिनका इसमें योगदान हो सकता है। वे सभी गुण और वो अवसर जो उस समय मेरे लिए उपयोगी थे, वे आज के छात्रों के लिए भी उपलब्ध हैं – नई चीजों को आजमाने के लिए अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ना, अपने साथ-साथ आसपास के लोगों के लिए अनुभव तलाशना, या जिस तरह से आप आसपास के लोगों का सम्मान करते हैं और उनके साथ समान व्यवहार करें। मैं इसके दार्शनिक पहलुओं के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन मैं इसके ठोस परिणामों पर चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि 1994 में, जब मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़ा था, उस वक्त ना आर्टिस्ट को पेश करने के लिए कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ करते थे ना ही हमारे बारे लिखने के लिए कोई मैगज़ीन हुआ करती थी और ना ही कोई हमारे तारीफ़ में इंडस्ट्री में बोल पाता था। कास्टिंग केवल इधर-उधर से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर की जाती

थी। काम की तलाश में लोगों तक पहुंचना एक कठिन प्रक्रिया थी और यह केवल भाग्य से ही संभव होता था। उस वक्त केबल चैनल शुरू हो गये थे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। जब मुझे टेलीविजन धारावाहिक 'यूल लव स्टोरी' में पहली भूमिका मिली, जहां मैंने एक अपराधी की भूमिका निभाई, तो इसका कारण डिफेंस पृष्ठभूमि से होने पर मेरे बालों का छोटा होना था। तो वहां से शुरू हुई थी मेरी कहानी। पर उस वक्त जो कि मैं इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं था, तो मैंने ज्यादा वक्त वहां के स्पॉटबॉयज़ और लाइटमैन के साथ बिताया। क्योंकि वे बिहार के थे, उनकी भाषा मुझे समझ आती थी और मेरी भाषा वो समझते थे। इन्ही लोगों ने मेरे काम की सराहना की और मेरी बहुभाषी (हिन्दी और तमिल) होने के बारे में विभिन्न निर्माताओं को मेरे नाम की सिफारिश की। मैं अपने करियर में मिले शुरुआती ब्रेक का श्रेय उन्हें दूंगा। जब मुझे मणिरत्नम के साथ पहली फिल्म मिली, तब तक मैं लगभग 1800 एपिसोड कर चुका था, जो की लगभग 300 फ़िल्मों के बराबर है। मैं इन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को एफटीआईआई में अपने छात्रों के साथ साझा करना चाहता हूं।

आज ओटीटी एक इक्वालाइज़र की तरह से आ गया है जहां एक साथ कई भाषाओं में फ़िल्में बनती हैं और रिलीज़ होती हैं हमारे घरों में आराम से उन्हें देखा भी जा सकता है। यह क्षेत्रीय और भाषागत बाधाओं को तोड़ रहा है। आप स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की इस शक्ति को कैसे देखते हैं और वे एफटीआईआई जैसे संस्थानों और सामान्य रूप से फिल्म निर्माण के लिए क्या पेशकश करते हैं?

मैं उस स्तर पर ओटीटी के पॉवर और पोटेंशियल को पहचानने का श्रेय खुद को दूंगा जब अन्य लोग इससे दूर ही रह रहे थे। शुरुआती चरण में, सीनियर अभिनेता इसे आज़माना नहीं चाहते थे। वास्तव में, समीक्षकों ने भी अपनी पेशेवर स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए इससे परहेज किया। लेकिन उन दिनों, मैंने एक सीरीज़ 'ब्रीथ' करने का फैसला किया, जिसे जबरदस्त रिस्पान्स मिला जिसने अंततः इन प्लेटफार्मों के प्रति इंडस्ट्री का पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया।

ओटीटी एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो है ही, जहां एक्सपोज़र के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। एक जमाने में ऐसा समझा जाता था की आपके पिक्चर की स्क्रिप्ट को कोई प्रोड्युसर नहीं मिल रहा तो उसे ओटीटी के लिए बना दो। ओटीटी की भाषा ही अलग है। एक एक्टर, सिनेमेटोग्राफ़र और ख़ासकर के स्क्रिप्ट राइटर्स और स्क्रीनप्ले राइटर्स के लिये इसका एप्रोच, साइंस और प्रोसेस ही एकदम अलग है। एक एक्टर को स्क्रिप्ट का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे एक निश्चित फॉर्मेट और ट्रीटमेंट में फिट किया जा सके जो कहानी कहने के लिए सबसे उपयुक्त हो, और यह तय करना होगा कि क्या यह एक ओटीटी फिल्म, एक श्रृंखला या एक सिनेमा बनने के योग्य है। अगर इस स्तर पर एक छोटी गलती भी हो जाये तो फिर प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश गुंजाइश नहीं होती। रेलवे मेन (माधवन की हालिया सीरीज़) को हम सिनेमा नहीं बना सकते थे क्योंकि

उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसके फॉर्मेट और स्टोरी टेलिंग के लिए हमें चार एपिसोड की ज़रूरत थी। एक एक्टर के हार्डवर्क के मुक़ाबले बाक़ी टेक्नीशियंस, स्क्रिप्टराइटर्स और डायलॉग राइटर्स को और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। हर सीरीज में एक सीरीज आर्क होता है, एक एपिसोडिक आर्क होता है और इस साइंस को सिखाने के लिए कुछ लोग चाहिए जो पहले खुद इसे समझें। यहां तक कि मैंने कहीं पर ये सुना था कि पश्चिमी देशों में कई जगह सिर्फ़ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए छह हफ्तों का कोर्स है जो ये सिखाते हैं कि स्क्रिप्ट को पढ़ा कैसे जाये और उनसे नॉन-टैन्जिबल (अमूर्त) तत्वों को कैसे निकाला जाए। ऐसे वर्णन जिसको आप स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते उसे ही नॉन-टैन्जिबल (अमूर्त) कहते हैं। जैसे ही वर्णन स्क्रिप्ट का हिस्सा बनता है, स्क्रिप्ट आगे बढ़ने की जगह रिजेक्ट हो जाती हैं। किसी स्क्रिप्ट में केवल उन्हीं तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता होती है जिन्हें स्क्रीन पर मूर्त रूप से दिखाया जा सके। तो इन चुनौतियों को समझना और उनसे जूझना आना हमारे एफ़टीआईआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओटीटी की प्रतिबद्धता लंबी है और इसमें एक जटिल कथानक काफ़ी लंबे एपीसोड्स में फैला हुआ है। छात्रों को बेहतर ढंग से प्रकशिष्ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और माध्यमों की प्रकृति और चुनौतियों को समझने पर जोर देते हुए प्रशिक्षण तदनुसार किया जाना चाहिए।

नई तकनीक और एआई के आगमन के साथ, हर क्षेत्र विकसित हो रहा है। नई भूमिकाएं बनाई जा रही हैं जबकि कुछ भूमिकाएं और कार्य कम उपयोगी होते जा रहे हैं। हम इस बदलते समय में हम कौशल उन्नयन और नए अंदाज में प्रस्तुति को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

बहुत अच्छा सवाल है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहानी कहने की जो कला है वो कभी नहीं बदलेगी। उसके स्वरूप और कहानी कहने की गति (पेसिंग) में बदलाव आ सकता है। कुछ लोगों को कहानी सुनानी आती है और कुछ लोग एक छोटा सा चुटकुला भी ढंग से नहीं सुना पाते। उसी तरीक़े से चूंकि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध है और आम आदमी की जो कंटेंट और सिनेमा को समझने की क्षमता है, वो बहुत बढ़ गई है और वो घर बैठे ही अपने मोबाइल या डिवाइस से अपना ख़ुद का कंटेंट बना देता है।

ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कम लागत वाली लेकिन बेहद आकर्षक और बाइट-आकार के कंटेंट जैसे कि रील्स, विकसित कर रहे हैं। वे इतने कम समय में ही अपने दर्शकों से जुड़ने और उनके अंदर उच्च स्तरीय भावनाएं जगाने में सक्षम हैं जो कि एक फ़िल्ममेकर एक पूरी फ़िल्म के माध्यम से ही दिखा पाता है। इस प्रकार के फ्री में उपलब्ध कंटेंट के साथ ही फ़िल्म मेकर्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसे ही आकर्षक फ़िल्में बनाये। एक समय पर जब सिनेमा लार्जर-देन-लाइफ़

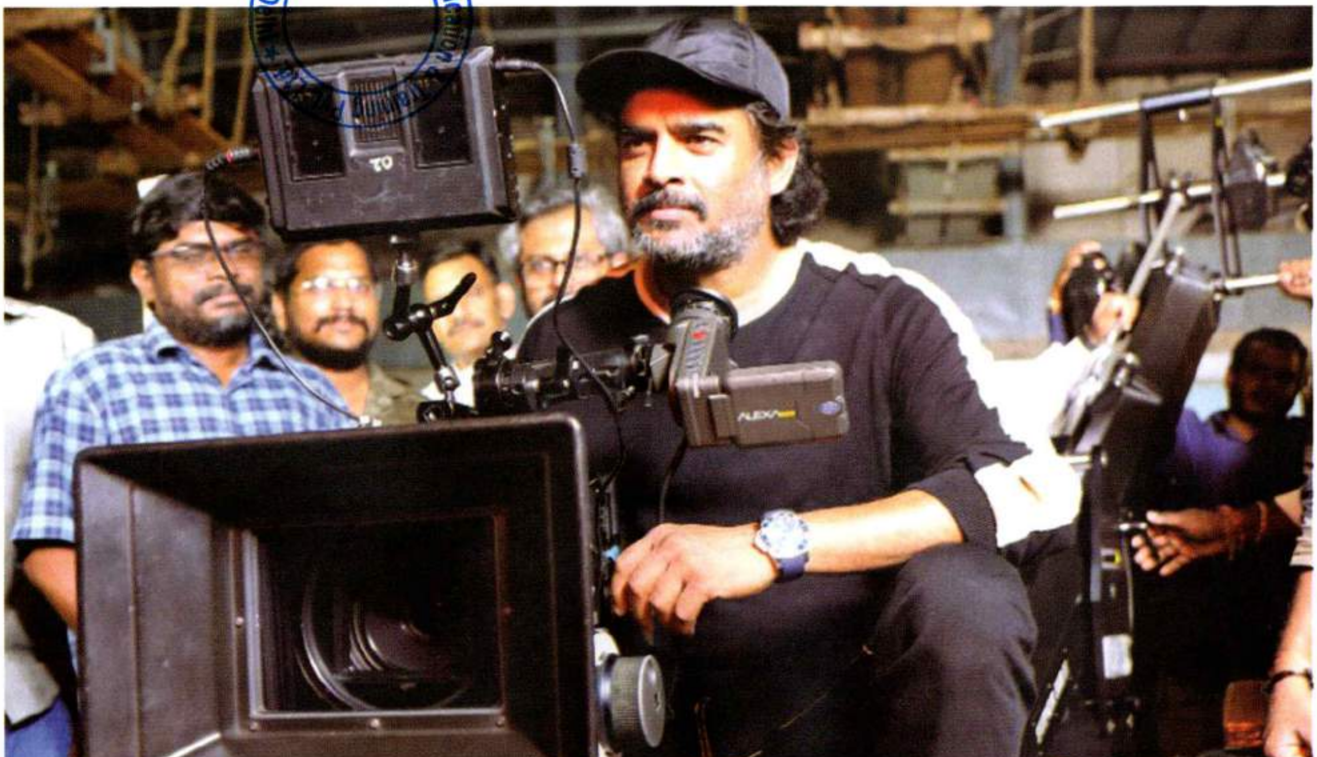

हुआ करता था और थिएटर में इसको काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता था। पर आज सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी और उन तक आसान पहुंच के वजह से दर्शक काफ़ी स्मार्ट हो गये हैं, सो बदलते समय के साथ फ़िल्म मेकर्स को भी खुद को बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हमेशा एक बुनियादी मंच प्रदान करेगी जिसका स्टैण्डर्ड बेहतर होता रहेगा। एआई सभी स्क्रीनप्ले लेखकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कहानी कहने के लिए इसका प्रभावी उपयोग ही किसी को अलग करता है और यह किसी की प्रतिभा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। 'घटोत्कच' की कहानी, कहानी कहने की कला के साथ 'हल्क' (अमेरिकी सुपरहीरो का किरदार) की कहानी जितनी ही आकर्षक और रोमांचक हो सकती है।

टेक्नोलॉजी ने लेवल प्लेइंग फ़ील्ड क्रिएट कर के साथ सबको कंटेंट बनाने का हक़ तो दे दिया पर हम लोकल कंटेंट और टैलेंट को बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर और बेहतर क्वालिटी कंटेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एफ़टीआईआई जैसे संस्थान क्या कुछ शॉर्ट-टर्म कोर्स प्रदान कर रहे हैं?

जी बिलकुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस चीज पर काम चल रहा है और कई जगहों पर हमनें इस पर अमल भी किया है। ऐसे कई शॉर्ट-टर्म कोर्स हैं, जो की ना केवल एफटीआईआई, पुणे में बल्कि अलग-अलग शहरों और राज्यों जैसे की जम्मू और कश्मीर तक जाकर कंडक्ट किए गए हैं ताकि आम आदमी को एफटीआईआई के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीखने का फ़ायदा मिले।

हम 75 ऐसे निःशुल्क शॉर्ट टर्म कोर्स करवा रहे हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। साथ ही हमारे ओपन लर्निंग प्लेटफार्म पर वर्ष 2017 से 15,000 से अधिक लर्नर जुड़ चुके हैं।

आपने बताया कि किस तरह से फ़िल्ममेकिंग में कोलैबोरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच के गैप को भरने के लिए और टैलेंट को इंडस्ट्री में अपना स्थान ढूंढने में मदद करने के लिए संस्थानों के द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

एफटीआईआई, उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि दुनिया के प्रीमियर इंस्टिट्यूशंस में से एक है। जिस प्रकार की सुविधाएं, कैंपस और उपकरण हमारे पास हैं, अगर उनका पूरा उपयोग किया जाये तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से से कंटेंट तैयार कर सकते हैं।

एफटीआईआई में लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी अगर लोगों को पता चले तो वो समझ जाएंगे की ये किस क्षमता के स्टूडेंट्स उनकी यूनिट में आ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की सख्त ज़रूरत है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जब हम आईआईटी और आईआईएम से लोगों को अपनी कंपनियों में शामिल करते हैं और उन्हें बड़ी सैलरी के साथ नौकरी देते हैं तो हम उनको सीधे सीईओ नहीं बनाते बल्कि उन्हें एक ट्रेनिंग पीरियड में डालते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखें, उनको समझें और सुधारें। फिर उनको सही मार्गदर्शन देकर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका कुछ सालों बाद भरपूर उपयोग कर पायें। पर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक सिनेमेटोग्राफ़र बन जाए तो पहले ही दिन से आप सीधा उस डिपार्टमेंट के सीईओ बन जाते हैं। आपके पास इंटरमीडिएट पीरियड नहीं है। हमारे छात्रों को यह समझने की आवश्यकता है कि आप एक पूर्ण डीओपी (फोटोग्राफ़ी निदेशक) बनने के लिए आवश्यक निपुणता और काबलियत आप में हो सकती है, लेकिन आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। आपको यह साबित करना होगा कि आप यूनिट के लिए एक एसेट हैं, और सिनेमा या सामग्री बनाने के स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी समूह में किसी व्यक्ति के पास तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित प्रतिभा नहीं हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति समूह का जीवन हो सकता है। अगर मुझे वह गुणवत्ता दिखे तो मैं उन्हें अपनी टीम में रखना चाहूंगा। निर्माता के रूप में, हम यह देखना चाहते हैं कि कितने छात्र टीम प्लेयर हैं। तो, ये पारस्परिक कौशल और क्षमताएं हैं जो किसी भी कलाकार या तकनीशियन के पास उस विभाग का नेतृत्व करने में सक्षम होने के लिए होनी चाहिए। यदि एफटीआईआई के छात्र या नियुक्ति करने वाली टीमें इसे समझ लें, तो मुझे लगता है कि समामेलन अधिक सहज और स्पष्ट हो जाएगा।

तो साथ-साथ इन सॉफ्ट स्किल्स को भी स्थापित करना ज़रूरी है?

ये बेहद ज़रूरी चीज है। ये हर संस्थान में ज़रूरी है। फ़िल्ममेकिंग में आपको गलती करने का एक ही मौका मिलता है। पहली

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd Delhi

फ़िल्म में भी गलती करने पर आपको कोई माफ़ नहीं करेगा, पूरी फ़िल्म गिर जाएगी। ये एक चांस है जो कोई नहीं लेना चाहेगा और बात ये है कि यहां कोई दूसरा चांस जैसा कुछ भी नहीं होता।

Elite Academies For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

ये ग्लोबल सिनेमा में बदलाव का दौर है। इस लेवल प्लेइंग ग्राउंड में भाषा, क्षेत्र और सीमा जैसी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं और अच्छा कंटेंट हर जगह उपलब्ध है तो इस माहौल में ग्लोबल मार्केट में इण्डियन कंटेंट अपने आप को कैसे स्थापित कर सकता है?

इसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास स्टोरीटेलर बनना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज है कि आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ कर आगे बढ़ें। आपको अब तक जो भी सिखाया गया है, उसको भूल कर और अपने आप को बिलकुल वल्नरेबल बना कर बदलते दौर के नये तौर - तरीके सीखने होंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं। के-पॉप कल्चर भारत के टीनेजर्स के बीच इतना लोकप्रिय हो चुका है कि वयस्क भी अब इस बदलते दौर में खुद को ढालने के लिए कोरियन भाषा सीखने लगे हैं।

तो हम अपने यहां के बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट कहां बना रहे हैं?

बिलकुल मैं वही कह रहा हूं। हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है कि हम अपने कंटेंट को इंटरनेशनल बन सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग इसे इस वजह से देख रहे, क्योंकि इनके परफॉरमेंस रीयलिस्टिक हैं, इनका स्क्रीनप्ले फास्टर है और उनकी फिलॉसफी से लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में ये ऑपोर्च्युनिटी हमें भी मिली हुई है। आपको बस हायर लेवल के स्किल्ड टेक्नीशंस को और एक्टर को लेकर उस टाइप का प्रोग्रेसिव कंटेंट बनाना है। आप सिर्फ़ स्टारडम पर भरोसा करोगे तो कुछ हद तक आप अपनी फ़िल्मों को लिमिट कर दोगे। आप भले ही काफ़ी पैसे खर्च कर दोगे पर वो फ़िल्म लिमिटेशन में ही बनेगी। कभी-कभी तो पैसा ही अच्छे प्रोजेक्ट्स को खराब कर देता है। प्रोजेक्ट में शामिल लोगों की इंटीग्रिटी को सही रखने के लिए आपको प्रोजेक्ट के सही बजट को भी जानना होगा। ये भी एक स्किल है।

आपने तो फ़िल्मों की कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। आपको भी फ़रहान (3 इडियट्स में माधवन का करैक्टर) की तरह इंजीनियर बनना था और आप आर्टिस्ट बन गये। तो आज की तारीख़ में इस फ़ील्ड में ऐसी टेक्निकल जानकारी और प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है?

मैं संक्षेप में इसको बताना चाहूंगा की अगर मेरे पास ये टेक्निकल ट्रेनिंग होती, अगर मुझे पहले ही पता होता कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करना होगा, अगर मैंने ये ट्रेनिंग की होती, तो मुझे लगता है कि जो काम मैंने 18-20 सालों में किया है वो बस छह सालों में कर पाता। बस इतना ही फ़र्क़ है।

जब मैंने शुरुआत की थी, उस वक्त स्क्रीन पर मुझे जो ग़लतियां करनी थी वो मैंने की और मैं बच भी निकला। अगर मैं अपने शुरुआती दिनों के अपने काम को देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने खुद को बचाया कैसे? मैं खुद को कहता हूं की 'तू तो यहां पर एक्टर है ही नहीं।' आपमें पोटेंशियल तो है पर आप स्क्रीन पर काफ़ी रॉ होते हैं। कभी-कभी तो ये चल जाता है पर कभी-कभी ये बहुत ही वाहियात लगता है। पर उस वक्त फॉरगिविंग फैक्टर काफी ज्यादा था। आप प्रोड्युसर के कॉस्ट पर भी सीख सकते थे। जैसा कि इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने कहा की मैंने टीवी के 1800 एपिसोड किए हैं। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार मणिरत्नम के साथ अपनी फ़िल्म कर रहा था और पीसी श्रीराम कैमरामैन थे। मेरे कैमरा और फ्रेम्स की पूरे परफेक्शन के साथ जानकारी ने उनको सरप्राइज कर दिया। तो वो एक सच्चा एक्सपीरियंस था और जब तक उन्होंने बताया नहीं तब तक खुद मुझे मेरे इस स्किल के बारे में पता नहीं था। आगे मुझे ये सब सिखाया जाता तो निश्चित ही ये जर्नी और छोटी होती।

पर आप हार्डवर्क को कम नहीं कर सकते। उस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए आपको जो हार्डवर्क करना होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक की आगे मुझे पहले ही पता चलता कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाला हूं और अगर मैंने भी ट्रेनिंग ली होती तो शायद मैं काफ़ी कम समय में बहुत अधिक सक्सेसफुल होता।

आपका कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न क्या है? आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या देखते हैं? आप ये सारी चीजें कहां से सीखते हैं?

मैं बहुत कम पढ़ता हूं। किसी कारण से मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता। पर मैं काफ़ी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर पाया हूं। मैं ये शुरू से ही समझ चुका था कि अगर मैं इंडस्ट्री के कम्फर्ट ज़ोन में ही रहूं तो मैं शायद

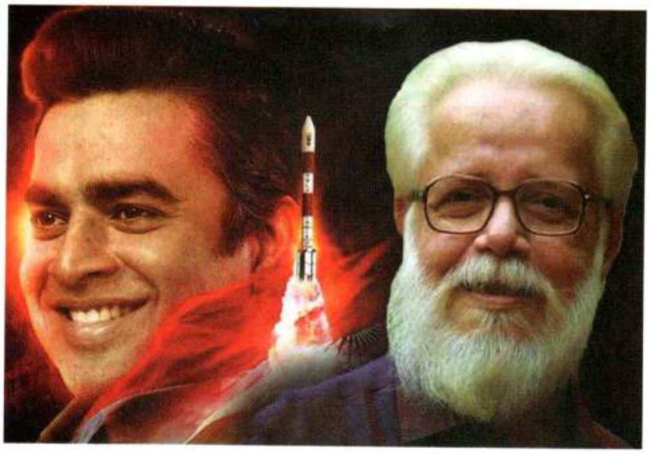

ग्रो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक जैसी कन्वर्सेशन करते हुए पाता हूं।

ये बात सभी पर लागू होती है, अगर कोई खुद को केवल अपने प्रोफेशन तक ही सीमित कर ले।

बिल्कुल। खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में आते ही बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी कम हो जाती है। आपको उस दुनिया से जुड़े रहने की जरूरत है जिनके लिए आप फ़िल्में बना रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि ऑटो रिक्शा की कीमत का किराया क्या है और उसमें क्या बदलाव हुए हैं तो वहीं आपने वो कनेक्ट खो दिया है। अन्य उद्योगों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप एक इंजीनियर हैं और आप इंजीनियरों के साथ इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हुए समय बिता रहे हैं, तो इसका आपके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

लेकिन फिल्म उद्योग में, जहां आप अपने दर्शकों के लिए एक कहानी बनाना चाहते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि समाज में क्या कुछ हो रहा है और ये कहां जा रहा है। इसलिए इस ज्ञान को हासिल करने के लिए मैं समय-समय पर अपने पेशे से ब्रेक लेता हूं। पिछले 14 सालों में मैंने सिर्फ 3-4 फिल्में ही की हैं। इस दौरान अनेक परिवर्तन हुए। सोशल मीडिया के बाद, लोगों ने अपना ज्ञान और चीजों को समझने के तरीके को बढ़ाया है। इन सभी घटनाक्रमों से अवगत होने के लिए हमें कुछ समय देने की जरूरत है। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूं और यह भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं विभिन्न पेशेवरों के साथ समय बिताऊं।

आमतौर पर एक 'स्टार' के प्रति उनके मन में जो प्रभाव और भय होता है, उससे बाहर आने और एक व्यक्ति के रूप में 'रियल मैडी' के साथ बातचीत करने में उन्हें थोड़ा समय लगता है। फिर धीरे-धीरे मुझे उनके पेशे के बारे में पता चलता है। चाहे वे आर्किटेक्ट हों, हाइड्रोपोनिक किसान हों, जैविक किसान हों, उनका कोई भी पेशा हो, वे मुझसे खुलकर बात करने लगते हैं। जब उनसे प्राप्त ज्ञान और अनुभव को हमारी फिल्मों में सफलतापूर्वक शामिल किया जाता है तो हम प्रासंगिक हो जाते हैं। जब मैं रॉकेट्री (द नांबी इफेक्ट) कर रहा था, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला। शुरुआत में मुझे निर्देशन पर भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने जिन पेशेवरों से मुलाकात की, उनसे तरल-ईंधन इंजनों के बारे में इतना कुछ सीखा कि मुझे एहसास हुआ कि केवल मैं ही यह कहानी बता सकता हूं। यह उस प्रकार का आत्मविश्वास है जो ज्ञान आपको देता है।

आप इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। मुझे विश्वास है कि एफटीआईआई के बच्चों को आपके इस अनुभव का फ़ायदा मिलता होगा। योजना की रीडर्स में एक बड़ी संख्या उनकी है जो कम्पेटिटिव एक्ज़ाम देते हैं। ये डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो बाद में सिविल सर्विसेज़ की भी तैयारी करते हैं। तो ये एक लंबी जर्नी होती है। उनमें कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं हैं और कुछ लोग नहीं। उनके लिए, डिपर पर्पस ऑफ़ लाइफ ढूंढना, सफलता का नया रास्ता बनाना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?

हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें एक डायलॉग है कि 'ऐ बुरे वक्त, अदब से पेश आ क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता।' मुझे ये बहुत अच्छी लाइन लगी। जितने भी लोग ये एक पल में अपना सारा कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है की उसके बाद भी एक पल है।

क्योंकि वो जिस किसी भी कम्पेटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे, उनके लिए जो भी उनका मक़सद है, बहुत सारे लोगों को वो पहले प्रयास में ही मिल जाता है। कुछ लोगों को ये नहीं भी मिल पाता है।पर हम आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी, आपका पूरा अचीवमेंट और आपकी पूरी कैपेबिलिटी सिर्फ़ कुछ घंटों में ही नहीं समझ पाते। यह संभव है कि उस वक्त तक आप अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाये हों या शायद आप उस दिन किसी और मानसिक परेशानी से जूझ रहे हों। मेरे विचार से ये किसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल की क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। कहते हैं कि गोल्फ के खेल में अगर आप गेंद को पूरी ताकत से मारते हैं तो वह उतनी दूर तक और बिलकुल सटीक नहीं जा पाती है। आपको 80 प्रतिशत पर शॉट्स मारने होंगे ताकि आप गेम अच्छे से खेल सकें और अपनी निरंतरता बनाए रख सकें। 80 प्रतिशत के इस सिद्धांत में कई दर्शन शामिल हैं। हर काम इस प्रकार से करें कि परिणाम से आप प्रभावित न हों।यदि आप 100 प्रतिशत हिट कर के भी वांछित परिणाम नहीं पाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद आप इसके लायक नहीं हैं। परीक्षा के दिन अपने जीवन का बोझ पूरी तरह से अपने कंधों पर न लें, जैसे कि आपका जीवन आपके जीवन के उस क्षण से ही परिभाषित होता है। यह इसके लायक नहीं है। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर व्यक्ति के पास एक कौशल होता है जो उसे लाखों में एक बनाता है। अपनी ताकत को खोजें। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

खेल कौशल ऐतिहासिक जीत का साल

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

एशियाई खेल 2022 हमारे देश के लिए एक ऐसे आयोजन के रूप में ऐतिहासिक रहे हैं, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इन खेलों में भारत ने 2018 के एशियाई खेलों की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक स्वर्ण पदकों के साथ 60 वर्षों में सर्वाधिक पदक (107) हासिल किए हैं और 16 नई खेल श्रेणियों में पदक जीते हैं। यह न केवल हमारी बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ का बल्कि खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का भी प्रमाण है जहां हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हासिल कुल पदकों में से लगभग 50 प्रतिशत पदक जीतने वाली हमारी महिला एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धि, उनके अटूट समर्पण, प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल मैदान पर उनके कौशल को दर्शाती है बल्कि सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने के लिए उनकी परिवर्तनकारी शक्ति और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती है। इन खेलों में महिला तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

भारतीय पैरा-एथलीटों ने भी पैरा एशियाई खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित 111 पदक जीत कर अब तक के सर्वाधिक पदकों के साथ इतिहास रचा है। इससे पहले भारत ने 2010

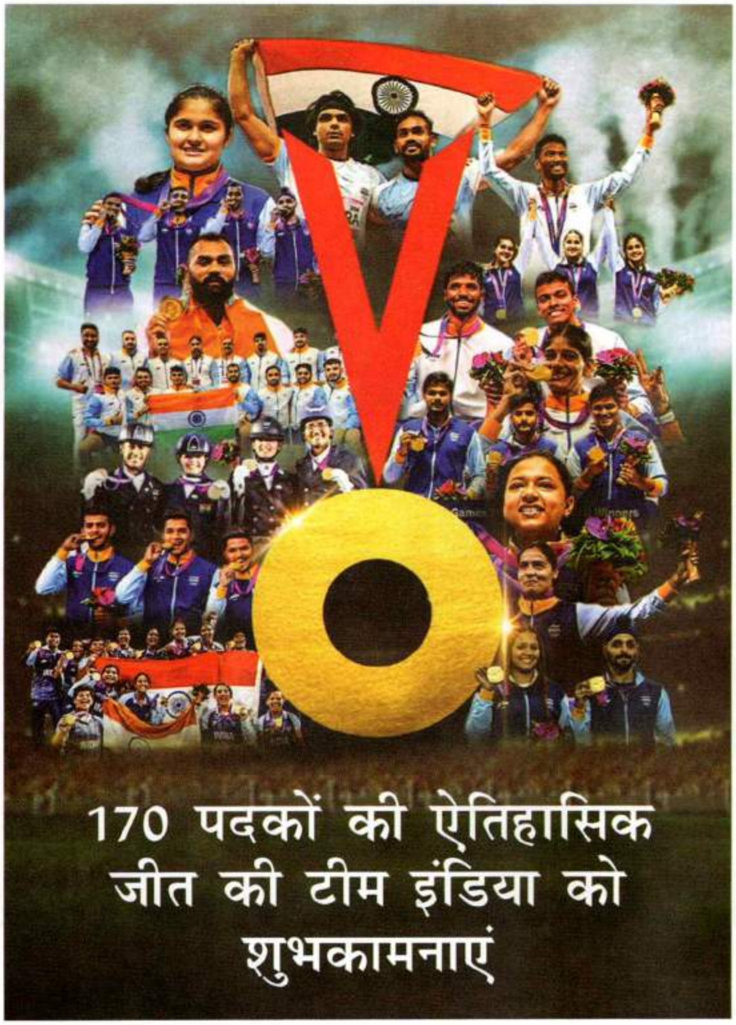

के खेलों में 14 पदक, 2014 में 33 पदक और 2018 में 72 पदक जीते थे। खेलों की शुरुआत के बाद से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां भारत समग्र पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। इन खेलों में भारत ने इस वर्ष खिलाड़ियों का अपना सबसे बड़ा दल भेजा, जिसमें 303 एथलीट (191 पुरुष और 112 महिला) शामिल थे।

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), एसएआई के प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी का विस्तार केंद्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) - (नियमित स्कूलों, स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट स्कूलों तथा अखाड़ों के लिए इसकी उप-योजनाओं के साथ) के तहत विशेषज्ञ प्रशिक्षक की सेवाएं, खेल उपकरण, भोजन तथा आवास, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वजीफा प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में शामिल विषयों में पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी, तीरंदाजी, कुश्ती, खो-खो आदि शामिल हैं।

आर प्रग्गनानंद ने भारतीय शतरंज के इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। वह विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे और भारतीय दिग्गज के साथ शीर्ष पर शामिल होने से एक जीत दूर थे।

भारत सरकार देश में खेल की एक संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक - खेलो इंडिया योजना - युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अपने पांच कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देती है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल दिखाने और प्रतिभाओं को तलाशने का बुनियादी मंच है। यह प्रतिभाशाली और गुणी बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की राह भी दिखाता है। इस योजना के 'टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट' लक्ष्य के तहत, खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 1.20 लाख रुपये आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता तथा कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, आहार, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं और बीमा शुल्क इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं के लिए 5.08 लाख रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह योजना उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करके उनका मार्ग प्रशस्त करती है। मंत्रालय प्रासंगिक राष्ट्रीय खेल महासंघों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसे विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन संगठनों के सहयोग से, राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं, अर्थात् खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन करता है।

टॉप्स (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम), युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक और प्रमुख कार्यक्रम है जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है।

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत को गौरवान्वित करने वाले विभिन्न एथलीटों की कहानियां देश में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत का ध्यान खेल प्रतिभाओं के विकास तथा फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर है। सरकारी सहायता और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से प्रेरित इस परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की उपस्थिति को और मजबूत किया है। ❑

(विभिन्न स्रोतों से)

भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शुभारंभ को चिह्नित करते हुए साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व-पश्चिम गलियारे की दो लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को 'दुहाई डिपो' से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारा की आधारशिला रखी थी।

आरआरटीएस एक नई रेल-आधारित, सैमी हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वैन्सी वाली कम्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। 180 कि.मी. प्रति घंटे की गति के साथ, आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी, क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वैन्सी तक जा सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तैयार किए जाने वाले कुल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन कॉरिडोर को चरण-I में लागू करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ कॉरिडोर; दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर; और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है, और यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा।

देश में विकसित आरआरटीएस एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय आवागमन का समाधान है, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समाधान से इसकी बराबरी की जा सकती है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी-मॉडल-एकीकरण होगा। इस तरह के परिवर्तनकारी क्षेत्रीय आवागमन समाधान क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे; रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेंगे; और वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी। ❑

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

2023 की झलकियाँ

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

जनवरी

- विश्व ने 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया
- 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित किया गया
- दुनिया की सबसे लंबी रिवरक्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन
- भारत विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन नागपुर में किया गया
- 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 21 अज्ञात द्वीप का नामकरण किया गया

फरवरी

- केंद्रीय बजट 2023-24 लोकसभा में पेश हुआ
- 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ
- भारत को अपनी संशोधित ड्रोन नीति मिली
- मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'आदि महोत्सव' नई दिल्ली में आयोजित किया गया
- नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ

KHELO INDIA YOUTH GAMES

मार्च

- बर्लिन, जर्मनी में आयोजित आईटीबी 2023 में अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीते
- उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के एक भाग के रूप में खेलो इंडिया, दस का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया
- एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (आईएलएमटी) का उत्तराखण्ड के देवस्थल में अनावरण किया गया
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) का सागरसेतु मोबाईल ऐप जारी किया गया

अप्रैल

- काशी तेलुगु समागम का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ
- राजस्थान की पहली वंदेभारत एक्सप्रेस सेवा अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हुई
- राष्ट्रपति भवन के दूसरे अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के 3 पद्मविभूषण, 5 पद्मभूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किये
- सार्वजनिक और निजी सहयोग दिशानिर्देशों का विवरण देनेवाली भारतीय अंतरिक्ष नीति पेश की गई

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

2023 की झलकियाँ

मई

पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विकसित 'संचार साथी' पोर्टल लॉंच किया गया

कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का अयोजन

प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू' से सम्मानित किया गया

जून

भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज, एमवी एम्प्रेस-चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना

नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परिक्षण किया गया

9वाँ अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया

वर्ष 2021 के लिए 'गांधी शांति पुरस्कार' गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया गया

जुलाई

चंद्रयान-3, 14 जुलाई को आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया

प्रधानमंत्री को पेरिस में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया

अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येन्द्र सिंह लोहिया को इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रचने के लिए सम्मानित किया गया

अगस्त

77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ मिलेगा

भारत ने इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित 20वीं आशियान-भारत के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया

चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के सतह पर सफलता पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग

2023 की झलकियाँ

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd ★ Delhi ★

सितम्बर

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने श्रीहरिकोटा रेंज से देश का पहला सौर मिशन, आदित्य एल1 प्रक्षेपित किया

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर 'यशोभूमि' का पहला फेज नयी दिल्ली में देश को समर्पित

नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम् में जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन सम्पन्न

नई दिल्ली में पहला हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परिचालन शुरू

अक्टूबर

9वां जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, यशोभूमि, द्वारका, दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन से पहले लाइफ़ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पर संसदीय फोरम आयोजित किया गया था

नई दिल्ली युवाओं के लिए 'मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) प्लेटफार्म का उद्घाटन हुआ

राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रदान किए

नवम्बर

देश में भव्य पैमाने पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया

भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग के इरादे के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आइटीपीओ, प्रगति मैदान में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू जीआई मंडप में 200 से अधिक अद्वितीय भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पाद प्रदर्शित किए गए

संयुक्त सैन्य अभ्यास " मित्र शक्ति अभ्यास- 2023" का 9वां संस्करण औंध (पुणे) में संपन्न हुआ

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना

- बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन
- 315,000 टूल-किट प्रोत्साहन
- गिरवी-रहित ऋण सहायता
  -एक लाख तक (पहली किस्त)
  - 72 लाख तक (दूसरी किस्त)
- डिजिटल लेन-देन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन

- योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्प को शामिल किया जायेगा
- बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण
- कारीगरों और शिल्पकारों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के द्वारा मान्यता

MY भारत

मेरा युवा भारत

भारत सरकार द्वारा युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जा रही है। ये प्लेटफार्म देश भर में युवा स्वयंसेवी अवसरों को मौद्रिक आदान-प्रदान के बिना केंद्रीकृत करता है तथा वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने के साथ-साथ एक केंद्रीकृत यूथ डेटाबेस बनाता है। यह तंत्र युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और 2047 तक अमृत भारत के निर्माण के लिए अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करेगा।

माई भारत पोर्टल के फायदे

- व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व विकास।
- सामुदायिक नेतृत्व और नवाचार के लिए युवा निवेश में वृद्धि।
- युवाओं के नेतृत्व वाले विकास और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- पहुंच के लिए फ़िजिटल वातावरण की स्थापना।
- एकीकरण के माध्यम से कार्यक्रम की प्रभावशीलता में वृद्धि।
- युवाओं और मंत्रालयों के लिए केंद्रीय संसाधन।
- युवाओं, सरकारी परियोजनाओं और हितधारकों के बीच बेहतर संचार।

पंजीकरण कैसे करें?

- ब्राउजर खोलें और टाइप करें mybharat.gov.in
- LOGIN स्क्रिन पर दाईं ओर ऊपर मौजूद लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपना मोबाइल नंबर डालें या फिर अन्य विकल्प जैसे कि यूजरनेम, ईमेल आदि का उपयोग करें।
- सहमति विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगइन और खुद को रजिस्टर करने के लिए साइनइन बटन पर क्लिक करें।

स्रोत: मन की बात पुस्तिका

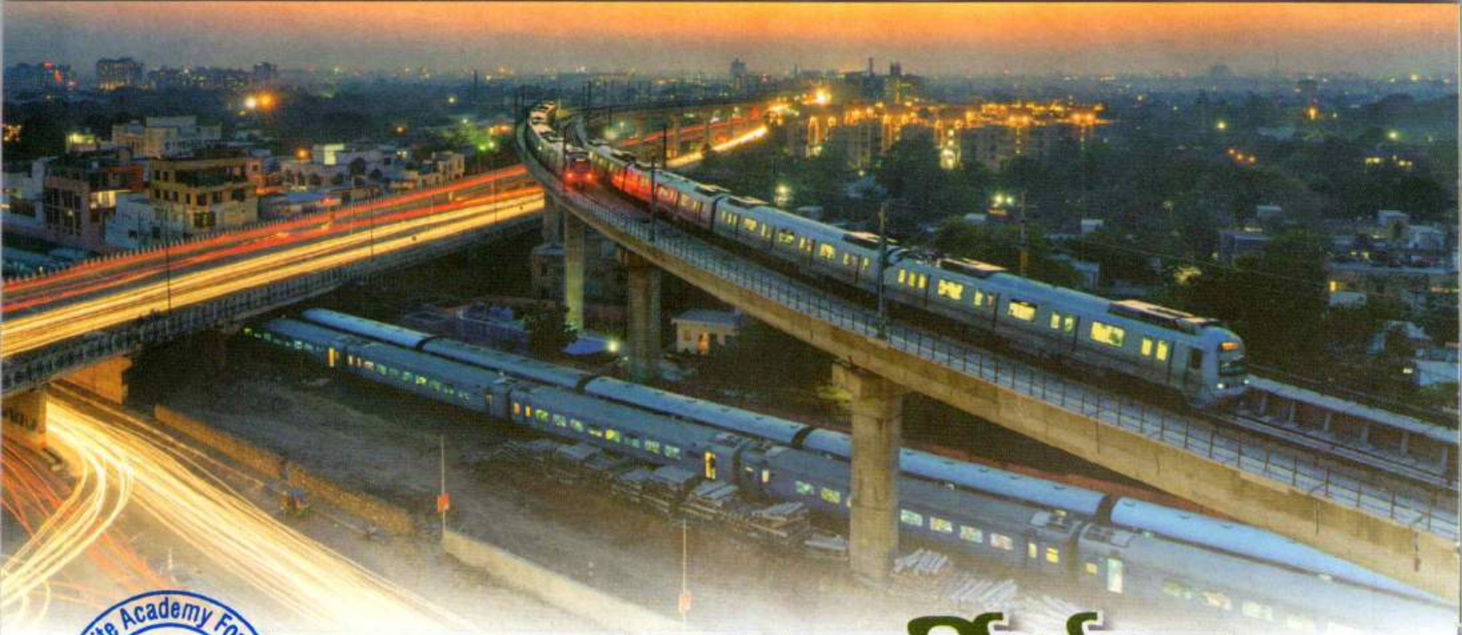

आवागमन का पुनर्निर्धारण
भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव

पीएम गति शक्ति - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, 2021 मूल रूप से आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक माध्यम से अन्य माध्यम तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे आधारभूत सुविधाओं को अंतिम दूरी तक पहुंचने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा।

परिवहन की एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली किसी देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय शिपिंग, हवाई परिवहन आदि सहित परिवहन के कई तरीके शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन ने नेटवर्क के प्रसार और सिस्टम के आउटपुट दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय परिवहन के विभिन्न तरीकों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

सड़क

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष संगठन है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण और रखरखाव; मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का प्रशासन; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008; पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात की आवाजाही की व्यवस्था करने के अलावा, सड़क परिवहन, पर्यावरणीय मुद्दों, ऑटोमोटिव मानदंडों आदि से संबंधित व्यापक नीतियों का निर्माण शामिल है। यातायात (यात्री और माल) को संभालने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में लगभग 62.16 लाख कि.मी. सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है।

Website : www.morth.nic.in

भारतमाला परियोजना

मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने, गैर-प्रमुख बंदरगाहों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों के विकास, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के विकास आदि के साथ-साथ सागरमाला के साथ एकीकरण की दृष्टि से एनएच नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है। भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम (एनएस-ईडब्ल्यू) गलियारों के साथ-साथ सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई की संभावना है। इसके अलावा, आर्थिक गलियारों, जीक्यू और एनएस-ईडब्ल्यू गलियारों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए लगभग 8,000 किलोमीटर के अंतर गलियारे और लगभग 7,500 किलोमीटर के फीडर मार्गों की पहचान की गई है। कार्यक्रम में शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए रिंग रोड/बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास इत्यादि की परिकल्पना की गई है।

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) 2016 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन शामिल है। इसे हरित राजमार्ग नीति के तहत लॉन्च किया गया था। पर्यावरण-अनुकूल और हरित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 2015 में इसे तैयार किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करना, क्योंकि वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करने में पेड़ों और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के अवशोषण का एक प्राकृतिक घटक माना जाता है, वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, तटबंध के ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकना, आदि परियोजना के उद्देश्यों में शामिल हैं। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की स्थापना एनएचएआई अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) सौंपी गई है, जिसमें अन्य छोटी परियोजनाओं के साथ, 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अनुबंध आवंटन और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुरूप हों, अनुबंधों के आवंटन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निविदा से जुड़े मानदंडों को अपनाना, परियोजनाओं का कार्यान्वयन सर्वोत्तम गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप हों, और राजमार्ग प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका रखरखाव करना सुनिश्चित हो। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एक्सप्रेसवे सहित) की कुल लंबाई 1,32,499 कि.मी. है। जबकि राजमार्ग/एक्सप्रेसवे सभी सड़कों की लंबाई का लगभग 1.7 प्रतिशत ही हैं, किंतु वे सड़क यातायात का लगभग 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

Website : www.nhai.gov.in

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च मानक तक उन्नत, पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की एक परियोजना है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 49,260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के काम और निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। एनएचडीपी को मौजूदा भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है।

पीएम गति शक्ति योजना

पीएम गति शक्तिः मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, 2021 मूल रूप से आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक माध्यम से अन्य माध्यम तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे आधारभूत सुविधाओं को अंतिम दूरी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। पीएम गति शक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd Delhi

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

व्यापकता: इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल होंगी। व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए अब प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता प्राप्त होगी;

अनुकूलन: राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए, योजना में लगने वाले समय समय और लागत के संदर्भ में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने में मदद करेगी;

विश्लेषणात्मकता: यह जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता मिल सकेगी;

सशक्तता: सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति का अवलोकन, समीक्षा और निगरानी कर सकेंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

पर्वतमाला परियोजना

यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे के विकास के लिए पर्वतमाला परियोजना-राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ, वाराणसी, उज्जैन जैसे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे विकसित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री और लाइसेंस रिकॉर्ड

मंत्रालय ने इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार को लेकर नागरिकों के लिए कई नीतियां बनाई हैं। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ने आरटीओ संचालन को सफलतापूर्वक स्वचालित कर दिया है और एक समेकित परिवहन डेटाबेस स्थापित किया है। इसके साथ ही, कई नागरिक और व्यापार-केंद्रित अनुप्रयोग भी लागू किए गए हैं। इस मिशन मोड प्रोजेक्ट के मुख्य पहलू दो प्रमुख अनुप्रयोग हैं-वाहन और सारथी। जहां वाहन देश भर में वाहन पंजीकरण, कराधान, परमिट, फिटनेस और संबंधित सेवाओं को समेकित करता है, वहीं सारथी ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल और संबंधित गतिविधियों की देखभाल करता है। इसे राज्य-विशिष्ट नियमों, कर संरचना आदि के साथ 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक आरटीओ में लागू किया गया है। डेटाबेस को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया है, डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। यह वर्चुअल कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, परमिट आदि को अधिकृत सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।

ई-टोलिंग

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल, शुल्क प्लाजा के माध्यम से यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और फास्टैग का उपयोग करके उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर लागू किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) सेंट्रल क्लियरिंग हाउस (सीसीएच) है।

रेलवे

रेलवे माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोनों से लोगों को एक साथ लाता है और व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थयात्रा और शिक्षा के संचालन को संभव बनाता है। 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, तब यह एक बहुत ही मामूली शुरुआत थी। तब यह सिर्फ 34 कि.मी. की दूरी तय करती थी। अब तो 7,308 स्टेशनों, 68,043 कि.मी. की रूट लंबाई में फैले भारतीय रेलवे 13,215 लोकोमोटिव, 74,744 यात्री सेवा वाहन, 10,103 अन्य कोचिंग वाहन और 3,18,896 वैगन के बेड़े के साथ विशाल नेटवर्क में विकसित हो गया है। इन अनेक वर्षों में भारतीय रेलवे का विकास अभूतपूर्व है। इसने देश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेटवर्क 68,043 रूट किलोमीटर तक फैला हुआ मल्टी-गेज ऑपरेशन चलाता है। रूट किलोमीटर का लगभग 74.06 प्रतिशत और रनिंग ट्रैक किलोमीटर का 80.38 प्रतिशत और कुल ट्रैक

किलोमीटर का 78.46 प्रतिशत विद्युतीकृत है। नेटवर्क को 17 जोन में बांटा गया है। डिवीजन इसकीआधारभूत परिचालन इकाइयां हैं। 17 जोन और उनके संबंधित मुख्यालय नीचे दिए गए हैं:

जोनल रेलवे	मुख्यालय
मध्य	मुंबई
पूर्व	कोलकाता
पूर्वी तट	भुवनेश्वर
पूर्व-मध्य	हाजीपुर
उत्तर	नई दिल्ली
उत्तर-मध्य	प्रयागराज
उत्तर-पूर्व	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमांत	मालीगांव (गुवाहाटी)
उत्तर-पश्चिम	जयपुर
दक्षिण	चेन्नई
दक्षिण-मध्य	सिकंदराबाद
दक्षिण-पूर्व	कोलकाता
दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे	बिलासपुर
दक्षिण-पश्चिम रेलवे	हुबली (हुबली)
पश्चिम	मुंबई
पश्चिम-मध्य रेलवे	जबलपुर

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

Website : www.indianrailways.gov.in

अनुसंधान और विकास

लखनऊ में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग है। यह तकनीकी मामलों में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह रेलवे निर्माण और डिजाइन से जुड़े अन्य संगठनों को भी परामर्श प्रदान करता है। आरडीएसओ ने सीएसआईआर-सीएसआईओ के सहयोग से एसी कोचों के लिए कोविड निवारक के रूप में यूवी-सी आधारित एंटी-वायरल और एंटी-पैथोजेन सिस्टम विकसित करके उसका इस्तेमाल किया है। इसने हाई स्पीड ऑटोमोबाइल कैरियर कोचों को भी विकसित और डिजाइन किया है, जिसमें दोपहिया, चार पहिया, एमयूवी, एसयूवी, ट्रैक्टर आदि की लोडिंग/अनलोडिंग की उन्नत विशेषताएं हैं, जिसमें 18 टन के उच्च पेलोड को पूरा करने की क्षमता और गति क्षमता 110 कि.मी. प्रति घंटा है।

रेलवे वित्त

रेलवे बजट भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का एक हिस्सा है, लेकिन 1924 के पृथक्करण सम्मेलन के कारण 1924-25 से रेलवे बजट को संसद में अलग से पेश किया जा रहा था। अनुदान के लिए रेलवे की अपनी 16 मांगें थीं, जिसे संसद द्वारा अलग से विचार किया जाता था और पारित किया जाता था। पृथक्करण कन्वेंशन के पीछे मुख्य कारण नागरिक अनुमानों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना था, क्योंकि रेलवे वित्त सामान्य वित्त का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। सरकार ने 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। एकीकृत बजट रेलवे के मामलों को केंद्र में लाता है और सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह विलय राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच मल्टीमॉडल परिवहन योजना की सुविधा प्रदान करता है।

वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय रेल द्वारा संचालित एक सेमी-हाईस्पीड, इलेक्ट्रिक मल्टीपल-यूनिट ट्रेन है। इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया था। इस तथ्य को उजागर करने के लिए 2019 में, इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। नई दिल्ली-कानपुर-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग के बीच अपनी तरह की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका परिचालन 2019 में शुरू किया गया। इसश्रृंखला में आठवां ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच परिचालित किया गया, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। वंदे भारत 2.0 की शुरुआत 2022 में गांधीनगर से मुंबई रूट के साथ हुई। सितंबर 2023 तक, देश भर में 50 वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं।

नौवहन मंत्रालय

नौवहन मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। समुद्री परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है। यह विकास की गति, संरचना और पैटर्न को प्रभावित करता है। 2020 में मंत्रालय का नाम बदलकर पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। मंत्रालय अपने दायरे में नौवहन और बंदरगाह क्षेत्रों को शामिल करता है, जिसमें जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह और अंतरदेशीय जल परिवहन भी शामिल हैं। यह नौवहन से संबंधित नियमों और विनियमों तथा कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। विदेशी व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके बर्थ और कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के संदर्भ में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान में इसकी क्षमता 1617.39 एमएमटी है।

Website : www.shipmin.gov.in

समुद्री विकास

भारत की लगभग 7,517 कि.मी. लंबा समुद्र तट है, जो मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी शेल्फ और द्वीपों के साथ-साथ फैली हुई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहां 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं। भारतीय नौवहन उद्योग ने वर्षों से परिवहन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

Elite Academy For Education Delhi

सागरमाला कार्यक्रम

समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करने के लिए, भारत सरकार ने देश में पोर्टेड विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के निवेश के साथ आयात-निर्यात और घरेलू व्यापार की रसद लागत को कम करना है। इसमें घरेलू कार्गो के परिवहन की लागत को कम करना; तट के निकट भविष्य की औद्योगिक क्षमताएं स्थापित करके थोक वस्तुओं की रसद लागत कम करना; बंदरगाह के निकट असतत विनिर्माण क्लस्टर आदि विकसित करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्देश्यों में बंदरगाह का आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी, तटीय सामुदायिक विकास आदि शामिल हैं।

प्रमुख बंदरगाह

उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं। बंदरगाह समुद्री परिवहन और भूमि-आधारित परिवहन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की लगभग 7,517 कि.मी. लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 205 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं। 6 प्रमुख बंदरगाह-कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार (एन्नोर), चेन्नई और वी.ओ. चिदंबरनार, पूर्वी तट पर हैं और अन्य प्रमुख बंदरगाह, जैसे, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मोर्मुगाओ, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (शेवा, नवी मुंबई) और दीनदयाल (तत्कालीन कांडला) पश्चिमी तट पर हैं। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और संघ सूची (संविधान की 7वीं अनुसूची) में शामिल हैं। प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह संबंधित समुद्री राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और समवर्ती सूची में शामिल हैं। सभी भारतीय बंदरगाहों द्वारा प्रबंधित कुल यातायात का, 55 प्रतिशत प्रमुख बंदरगाहों द्वारा और 45 अन्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

अंतरदेशीय जल परिवहन

भारत में लगभग 14,500 कि.मी. लंबा नौगम्य अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क है। अंतरदेशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) एक ईंधन-कुशल, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाला परिवहन का माध्यम है। हालांकि, इसके माध्यम से माल परिवहन वर्तमान में देश में कुल माल परिवहन का 2 प्रतिशत से भी कम है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की स्थापना 1986 में देश में शिपिंग और नेविगेशन के प्रयोजनों के लिए अंतरदेशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए की गई थी। परिवहन के एक पूरक साधन के रूप में आईडब्ल्यूटी, जलमार्गों के माध्यम से कुछ थोक माल को मोड़कर भीड़भाड़ वाली सड़क और रेल परिवहन के साधन को कम करने में मदद कर सकता है। सरकार ने आईडब्ल्यूटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 24 राज्यों में फैले 111 (5 मौजूदा और 106 नए सहित) राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) की घोषणा की। विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी खंड पर राष्ट्रीय जलमार्ग-I की क्षमता वृद्धि के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित की जा रही है।

नागर विमानन

किसी देश के समान विकास के लिए हवाई परिवहन महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। यह उन क्षेत्रों में से एक है जो अपने प्रत्यक्ष और उत्प्रेरक गुणक प्रभावों के माध्यम से अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को प्रमुखता से प्रभावित करता है। नागर विमानन मंत्रालय अपने दायरे में देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हवाई परिवहन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, गैर-वाणिज्यिक उड़ान और नागरिक उड्डयन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम, 1937, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, वायुयान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 और नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अन्य कानूनों का प्रबंधन करता है। यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन, 1944 ('शिकागो कन्वेंशन') को पूरा करने के लिए कानून तैयार करता है। मंत्रालय नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित संधियों, सम्मेलनों और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। विशेष रूप से, यह अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित हवाई सेवाओं के संचालन के लिए अन्य देशों के साथ हवाई सेवा समझौता करता है।

Website : www.civilaviation.gov.in

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 में की गई थी। आरसीएस-उड़ान का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और हवाईअड्डा संचालकों द्वारा रियायतें जैसे उपाय करना है और ऐसे मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) का प्रावधान करके जनता के लिए इसे किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना/प्रोत्साहित करना है। इस योजना में मौजूदा हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर-सेवित हवाई अड्डे और अल्पसेवित हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

पहली आरसीएस-उड़ान की उड़ान का शुभारंभ 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए किया गया था। 2016 में उड़ान के लॉन्च होने तक, भारत में निर्धारित परिचालन वाले 74 हवाई अड्डे थे, जबकि योजना के शुरू होने के बाद पिछले छह वर्षों के दौरान, विभिन्न एयरलाइनों को 1,300 वैध मार्ग प्रदान किए गए हैं, 75 असेवित और अल्प-सेवित हवाई अड्डों (9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे सहित) को जोड़ने वाले 495 मार्ग (10 अक्टूबर 2023 तक) चालू हो गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), वैधानिक रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित किया गया था, जिसे पूर्ववर्ती अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के विलय द्वारा बनाया गया था। एएआई की प्राथमिक जिम्मेदारी हवाईअड्डों और सिविल एन्क्लेवों का प्रशासन और समेकित प्रबंधन है जहां हवाई परिवहन सेवाएं संचालित होती हैं/संचालित करने का इरादा है और हवाईअड्डों की स्थापना में सहायता करने या कनेक्ट करने के उद्देश्यों के लिए सभी वैमानिक संचार स्टेशनों का प्रशासन और समेकित प्रबंधन है। एएआई को हवाई नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान सहित भारतीय हवाई क्षेत्र के नियंत्रण और प्रबंधन का काम सौंपा गया है। एएआई द्वारा प्रबंधित भारतीय हवाई क्षेत्र का माप लगभग 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील है, जिसमें लगभग 1.0 मिलियन वर्ग समुद्री मील का भूमि क्षेत्र और लगभग 1.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील का समुद्री हवाई क्षेत्र शामिल है। एएआई 133 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 23 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (3 सिविल एन्क्लेव सहित), 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे (4 सिविल एन्क्लेव सहित) और 100 घरेलू हवाई अड्डे (22 सिविल एन्क्लेव सहित) शामिल हैं।

Website : www.aai.aero

विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण

विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। एईआरए को हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को विनियमित करने और हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक के रूप में, एईआरए का लक्ष्य समान अवसर पैदा करना, सभी प्रमुख हवाई अड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हवाई अड्डे की सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना और वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना है। इसके कार्यों में वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि का निर्धारण, विमान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत लगाए गए यात्री सेवा शुल्क की राशि का निर्धारण और निर्धारित प्रदर्शन मानकों की निगरानी करना शामिल है। सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित, जैसा कि सरकार या इसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

Website : www.aera.gov.in

अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी

भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एक विस्तृत नेटवर्क संचालित करता है और वर्तमान में 116 देशों के साथ हवाई सेवा समझौता है। भारत वर्तमान में 52 से अधिक देशों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जबकि 100 से अधिक देशों को अप्रत्यक्ष मार्गों से जोड़ता है। विदेशों से कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए, हवाई सेवा समझौते के संदर्भ में विदेशी वाहकों को नामित किया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के संदर्भ में, ओपन स्काई व्यवस्था 6 भारतीय मेट्रो हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से सीधे मौजूदा द्विपक्षीय अधिकारों के अलावा असीमित उड़ानों की अनुमति देती है। अक्टूबर 2023 तक, भारत ने 24 देशों के साथ खुले आकाश की व्यवस्था की है। भारत ने रूस के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें घरेलू कोड शेयर के लिए पॉइंट्स ऑफ कॉल साझा किए गए, क्षमता पात्रता बढ़ाई गई और रूसी वाहकों के लिए मार्ग-वार प्रतिबंध हटा दिए गए।

बायोमेट्रिक समर्थित निर्बाध यात्रा

डिजीयात्रा नीति यात्रियों को मल्टीपल टच प्वाइंट पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

इसमें चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित, निर्बाध प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य विवरण (पीआईआई) और यात्री की आईडी और यात्रा विवरण केंद्रीय रूप से संग्रहीत नहीं होते हैं बल्कि यात्री के स्मार्टफोन में एक सुरक्षित वॉलेट में संग्रहीत होते हैं। उपयोग के 24 घंटे के भीतर डेटा मिटा दिया जाता है। यह सेवा फिलहाल केवल घरेलू उड़ानों के लिए शुरू की गई है और यह स्वैच्छिक है। डिजीयात्रा ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अक्टूबर, 2023 तक यह 13 हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कोच्चि और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर चालू है।

जीपीएस समर्थित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन)

गगन एक सहयोगी प्रणाली है जिसे विशेष रूप से नागरिक उड्डयन में सटीक दृष्टिकोण के लिए जीपीएस सिग्नल की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह 2015 से पूर्ण परिचालन में है और चौबीसों घंटे (24x7) उपलब्ध है।

कृषि उड़ान 2.0

कृषि उड़ान 2.0 योजना भारतीय मालवाहक और यात्री से कार्गो के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज (टीएनएलसी), और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) की पूर्ण छूट प्रदान करके हवाई परिवहन द्वारा कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में शुरू की गई थी। चयनित हवाई अड्डों पर, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्र और द्वीपों और अन्य चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य देश के विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली सभी कृषि उपज के लिए निर्बाध, किफायती, समयबद्ध, हवाई परिवहन और संबंधित रसद सुनिश्चित करना है। इस योजना में देश के कुल 58 हवाई अड्डे शामिल हैं। पहचाने गए कुल 58 हवाई अड्डों में से 25 पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों में और 33 हवाई अड्डे अन्य क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं।

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, नागर विमानन मंत्रालय ने लोगों को व्यापक पहुंच मानकों को समझने में सहायता करने के लिए 'नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए पहुंच मानक और दिशानिर्देश' प्रकाशित किए हैं। हवाई यात्रा में पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हवाई अड्डों पर पहुंच सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ लोगों, बच्चों, गर्भवती माताओं और विभिन्न अन्य उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हवाई यात्रा को सभी के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके। यह पहल सभी यात्रियों के अधिकारों और सम्मान का समर्थन करके हवाई यात्रा को अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक बनाने के प्रयास को दर्शाती है। ❑

(स्रोत: भारत वार्षिक संदर्भ ग्रंथ)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केन्द्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

भारत का उद्योग क्षेत्र

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतरविषयी, अंतरक्षेत्रीय, बहुक्षेत्राधिकारीय और विस्तृत नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित किया है। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य समेकित अवसंरचना विकास है, तो एनएलपी का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सुचारू बना कर और समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए लॉजिस्टिक्स सेवाओं और मानव संसाधनों में कार्यकुशलता लाना है।

लॉजिस्टिक्स की कार्यकुशलता बढ़ाने और खर्च घटाने तथा देश में अंतरविभागीय विभाजनों को तोड़ने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि विभिन्न एजेंसियों के योजना निर्माण और अवसंरचना विकास के प्रयासों को एकीकृत किया जाए। वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति इसी दिशा में एक कदम है। इसमें समग्र शासन के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। एकीकरण, तालमेल, प्राथमिकता निर्धारण और अधिकतम परिणाम को हासिल करने के लिए इसके दो पहलू हैं। इनमें से पहला भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का विकास है। इसके तहत सड़कों से लेकर रेलवे, विमानन, कृषि, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक को जोड़ा जा रहा है। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विभाग को सही और सटीक सूचना समय पर उपलब्ध हो। दूसरा पहलू तीन स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के जरिए बहुविध अवसंरचना और आर्थिक क्षेत्र के तालमेल के साथ विकास के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यवस्था करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 में शुरू की गई थी। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंत:विषय, क्रॉस-सेक्टोरल, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करती है। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

की पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की परिकल्पना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नियामक ढांचे, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को मुख्यधारा में लाने और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाकर लॉजिस्टिक्स सेवाओं और मानव संसाधनों में दक्षता लाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, संपूर्ण, कम लागत वाला, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नीति तैयार करने वाला मुख्य विभाग है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित धन के आधार पर, भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा का रखरखाव और प्रबंधन भी करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की दृष्टि से, एक उदार नीति लागू की गई है जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। जून 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के बाद, एफडीआई की मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें मौजूदा एफडीआई नीति और फेमा के तहत एफडीआई के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उस पर सरकार की मंजूरी से संबंधित कार्य अब संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दायर किए गए आवेदनों की मंजूरी की सुविधा के लिए विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ) का प्रबंधन और संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अगस्त 2022 से, एफआईएफ पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है और सरकारी मंजूरी की आवश्यकता वाले एफडीआई प्रस्ताव एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाते हैं।

Website : www.nsws.gov.in

मेक इन इंडिया

'मेक इन इंडिया' पहल 2014 में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह अनूठी पहल 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों में से एक है, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा दिया। यह विचार मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का है। इस पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 27 सेवा क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय करता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और देश में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों

में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश संबंधी गतिविधियां की जाती हैं।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना)

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं की घोषणा की गई। इससे, अगले 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि की उम्मीद है। पीएलआई योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना हैं ताकि वे वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकें और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के अनुकूल बन सकें।

स्टार्टअप इंडिया

'स्टार्टअप इंडिया' पहल 2016 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नए स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पहल उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों यानी (क) सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, (ख) वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन, और (ग) उद्योग-अकादमिक साझेदारी और बिजनेस इन्क्यूबेशन में मदद उपलब्ध कराती है। इस पहल की शुरुआत के बाद से, मौजूदा नीति पारिस्थितिकी तंत्र में कई रणनीतिक संशोधन पेश किए गए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 15 मई 2023 तक, 674 जिलों में 57 क्षेत्रों में कुल 99,371 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। 2016 से देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक स्टार्टअप ने 10.49 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की। इस योजना का उद्देश्य नवाचार-संचालित उद्यमिता में तेजी लाना और स्टार्टअप के लिए बड़े स्तर पर इक्विटी जुटाना जैसे संसाधन शामिल है। एफएफएस सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से बढ़ते भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा निवेश करते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 945 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) भी बनाई है। यह योजना स्टार्टअप की अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 300 इनक्यूबेटरों के माध्यम से लगभग 3,600 उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।

भारी उद्योग

भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोबाइल, पूंजीगत सामान और भारी विद्युत उपकरण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करता है और विनिर्माण, परामर्श और अनुबंध सेवाओं और चार स्वायत्त संगठनों में लगे 29 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) का प्रबंधन करता है। 2021 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भारी उद्योग मंत्रालय के प्रमुख क्षेत्रों में से एक उद्देश्य घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और नागरिकों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, टिकाऊ और किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि देश में गतिशीलता के परिदृश्य को बदला जा सके। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसों जैसे वैकल्पिक समाधान पारंपरिक ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल परिवहन प्रणाली के इस्तेमाल को कम करने में मदद करेंगे और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आधारित प्रणालियों के उपयोग को सक्षम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में परिवर्तन से विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी, तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण स्वच्छ होगा। भारी विद्युत उपकरण उद्योग ऊर्जा क्षेत्र और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। बॉयलर, टर्बो जनरेटर, टर्बाइन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, रिले और संबंधित सहायक उपकरण जैसे प्रमुख उपकरण इस उद्योग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। यह उद्योग देश के बिजली क्षमता वृद्धि कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, बाजार का रुझान भारत में बिजली क्षेत्र की आवश्यकता से प्रेरित है। प्रमुख बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) भारी विद्युत उपकरण उद्योग को आपूर्ति करने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र है।

Website : www.heavyindustries.gov.in

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है और देश में राष्ट्रीय आय और धन का समान वितरण सुनिश्चित

होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और साथ ही मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत क्षेत्र की कल्पना करता है। एमएसएमई के प्रचार और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। राज्यों में उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करने में मंत्रालय और उसके संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उद्यमियों की सुविधा के लिए दिशानिर्देशों के साथ, विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए 2020 में एक नया वर्गीकरण अधिसूचित किया गया था। समग्र मानदंड ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच अंतर को हटा दिया, इसके अलावा पहले के मानदंड में टर्नओवर का एक नया मानदंड जोड़ा जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित था। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एमएसएमई को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: (ए) एक सूक्ष्म उद्यम वह हैं जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; (बी) लघु उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और (सी) एक मध्यम उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए जनवरी, 2023 में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है।

Elite Academy for Education & Training, Delhi

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र

भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, छह करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ, अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27 प्रतिशत और भारत के निर्यात में लगभग 44 प्रतिशत और योगदान देने के साथ साथ 11.10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र ही ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने दायरे का विस्तार करने के साथ साथ, घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को साकार किया जा सके।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने जुलाई, 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (www.udyamregistration.gov.in/) प्रारम्भ किया। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। यह पोर्टल को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), आयकर, जीएसटी, टीआरईडी और एनसीएस (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य जीएसटीआईएन रखने से छूट प्रदान की है।

Website : www.msme.gov.in

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई थी, और 1987 और 2006 में संशोधित, यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने का कार्य कर रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। केवीआईसी की ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति निवेश पर संवहनीय गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए विकेंद्रीकृत क्षेत्र में एक बड़े संगठन के रूप में पहचान की गई है।

Website : www.kvic.gov.in

कपड़ा

कच्चे माल के विशाल भंडार और मूल्यश्रृंखला में उत्पादन क्षमता के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। इस उद्योग की विशिष्टता है कि इसमें हाथ से बुने हुए कपड़ों के और बड़ी पूंजी के साथ मिल से बने कपड़ों दोनों में ही भारतीय कपड़ा उद्योग की ताकत निहित है। यह 50 मिलियन से अधिक स्पिंडल और 8,42,000 रोटर्स की स्थापित क्षमता वाला 3,400 कपड़ा मिलों वाला दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा मिल क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने की पावरलूम इकाइयों जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण

और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। कपड़ा उद्योग का देश की कृषि, संस्कृति और परंपराओं के साथ गहरा संबंध है, जो घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए उनकी मांग के अनुरूप बहुमुखी उत्पादों का उत्पादन करता है। मूल्य के संदर्भ में भारतीय कपड़ा उद्योग कुल उद्योग उत्पादन में 7 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में 2 प्रतिशत और देश की निर्यात आय में 15 प्रतिशत योगदान देता है। 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देने के साथ ही, यह उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

Website: www.texmin.nic.in

इस्पात

इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग के विकास और योजनाएं तैयार करने का कार्य करता है। मंत्रालय लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो-मिश्र धातु, स्पंज आयरन आदि जैसे आवश्यक धातुओं के विकास और अन्य संबंधित कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। 2013-14 से कच्चे इस्पात के उत्पादन और क्षमता में निरंतर वृद्धि देखी गई है। यह उद्योग देश में औद्योगिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। मौजूदा समय में भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता तेजी से बढ़कर 142 मीट्रिक टन हो गई है, जिसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता भी लगातार बढ़कर 161.30 मीट्रिक टन हो गई है। तेजी से बढ़ता हुआ घरेलू इस्पात उद्योग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसका निर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूंजीगत सामान, रक्षा, रेल इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है।

Website : www.steel.gov.in

उर्वरक

उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दायरे में आता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन हो सके। विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग की योजना, प्रचार और विकास, उत्पादन की योजना और निगरानी, उर्वरकों का आयात और वितरण तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबंधन शामिल है।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) विभाग के अधीन कार्य करता है। यह उर्वरक विभाग के अंतर्गत 9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) का प्रबंधन भी करता है। विभाग ने उर्वरक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनका उद्देश्य उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

Website: www.fert.nic.in

रसायन और पेट्रो-रसायन

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अधीन था, फिर इसे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन लाया गया। 1991 में, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग को रसायन और उर्वरक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस विभाग को रसायन, पेट्रो-रसायन और फार्मास्युटिकल उद्योग क्षेत्र की योजना, विकास और नियमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से अन्य विभागों को आवंटित किए गए को छोड़कर; कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रशासन को छोड़कर कीटनाशक; सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को आवंटित नहीं किए गए हैं; पेट्रोकेमिकल्स; सिंथेटिक रबर के उत्पादन से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और उन्हें सहायता देने का काम शामिल हैं।

Website : www.chemicals.nic.in

औषधि विभाग (फार्मास्यूटिकल्स)

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। 2022-2023 के लिए फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार 3,79,450 करोड़ रुपये है। पिछले नौ वर्षों में, यह क्षेत्र 6.4 प्रतिशत की सीएजीआर (कुल फार्मा निर्यात के अनुसार) के साथ लगातार बढ़ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का कुल निर्यात 1,94,254 करोड़ रुपये का है और 2022-23 के लिए (थोक दवाओं, दवा मध्यवर्ती, दवा फॉर्मूलेशन, जैविक के लिए) फार्मास्यूटिकल्स का कुल आयात 56,391 करोड़ रुपये का है।

Website : www.pharamaceuticals.gov.in

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), देश का प्रमुख पृथ्वी विज्ञान संगठन है। यह सरकार को उद्योग और भूवैज्ञानिक क्षेत्र के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराता है। जीएसआई ने 1851 में मुख्य रूप से कोयले के अनुसंधान में लगे एक विभाग के रूप में शुरुआत की थी। इस विभाग ने पिछले 163 वर्षों में अपनी गतिविधियों का कई गुना विस्तार किया है और यह राष्ट्र निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में अभूतपूर्व रूप से बढ़े इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट और बिजली जैसे उद्योग राष्ट्रीय विकास में जीएसआई के योगदान की स्पष्ट गवाही देते हैं।

Elite Academy for Education Delhi Training Pvt.

जीएसआई अब पिछली डेढ़ सदी में विकसित सबसे बड़े और सबसे व्यापक पृथ्वी विज्ञान डेटाबेस में से एक का संरक्षक है। जमीनी, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और ज्ञान आधार का निर्माण और अद्यतनीकरण और उनका प्रसार जीएसआई के प्राथमिक लक्ष्य हैं। जीएसआई के वर्तमान गतिविधियों में सतह मानचित्रण; हवाई और सुदूर संवेदन सर्वेक्षण; अपतटीय सर्वेक्षण; खनिज और ऊर्जा संसाधनों की खोज; इंजीनियरिंग भूविज्ञान; भू-तकनीकी जांच; भू-पर्यावरणीय अध्ययन; जल संसाधनों का भूविज्ञान; भू-खतरा अध्ययन; अनुसंधान और विकास; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; और सूचना सेवाएं आदि शामिल हैं। 1:50,000 पैमाने पर आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा लगभग पूरे देश के लिए मौजूद है; भू-रासायनिक और भूभौतिकीय विषयों पर समान डेटा उत्पन्न करने के प्रयास जारी हैं। सार्वजनिक भूविज्ञान में अन्य गतिविधियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन और संवर्द्धन पर अब प्रमुख जोर देने वाला क्षेत्र बन गया है। जीएसआई के दो अन्य प्रमुख कार्य भूविज्ञान ज्ञान का प्रसार और क्षमता निर्माण करना है। जीएसआई एक क्षेत्र मिशन हाइब्रिड मैट्रिक्स के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें छह भौगोलिक रूप से वितरित क्षेत्र (मध्य, पूर्वी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी) हैं जो प्रशासनिक कार्यक्षेत्रों और पांच मिशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन क्षेत्रों में खास जोर दिया जाना है, यह उनका प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न गतिविधियों को नामित करते हैं।

Website : www.gsi.gov.in

भारतीय खान ब्यूरो

मार्च 1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और लघु खनिजों के अलावा अन्य खनिज संसाधनों के संरक्षण और व्यवस्थित दोहन के लिए वैधानिक और विकासात्मक जिम्मेदारियों के साथ खान मंत्रालय के अधीन एक बहु-विषयक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है।

भारतीय खान ब्यूरो 2015 में संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रवर्तन के तहत बनाए गए नियमों; खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016; और अन्य नए नियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत नियामक कार्य करता है। यह लाभकारी अयस्क और पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन और खनन भूवैज्ञानिक के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक, तकनीकी-आर्थिक, अनुसंधान का अध्ययन करता है। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खनन और खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरी इकाई मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमइसीएल) खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में काम कर रही है।

Website : www.ibm.gov.in ❑

स्रोत: (भारत वार्षिकी)

NITI Aayog

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

प्रधान मंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन (पीवीटीजी)

बजट आवंटन

- सरकार ने बजट 2023-24 में प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- आवंटन तीन साल तक चलता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना का हिस्सा है।

मिशन के उद्देश्य

- मिशन का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का उत्थान है।
- इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, और टिकाऊ आजीविका जैसे आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है।

फ़ील्ड अवलोकन

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी पीवीटीजी क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा करते हैं।
- सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर।
- रिपोर्ट आजीविका के अवसरों में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

नोडल मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय

योजना का विवरण www.stomis.gov.in पर उपलब्ध है।

स्रोत: पीआईबी

मेरी माटी मेरा देश

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जन भागीदारी की भावना में इस अभियान में पंचायत/गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में आयोजित कई गतिविधियां और समारोह शामिल हैं। गतिविधियों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुरों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए शिलाफलकम (एक स्मारक) का निर्माण शामिल था; शिलाफलकम में लोगों द्वारा 'पांच प्रण' की शपथ लेना; स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाना और 'अमृत वाटिका' (वसुधा वंधन) विकसित करना, और स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह (वीरों का वंदन), आदि।

इस अभियान को व्यापक रूप से सफलता मिली, जिसमें 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.3 लाख से अधिक शिलाफलकम बनाए गए; पांच प्रण लगभग 4 करोड़ शपथ वाली सेल्फी अपलोड की गई। देशभर में 2 लाख से अधिक 'वीरों का वंदन' कार्यक्रम आयोजित किए गए; 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए हैं; और देश भर में वसुधा वंदन थीम के तहत 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गईं।

'मेरी माटी मेरा देश' अभियान में अमृत कलश यात्रा भी शामिल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों से मिट्टी (मिट्टी) और चावल के दानों का संग्रह शामिल है, जिसे ब्लॉक स्तर (जहां ब्लॉक में सभी गांवों की मिट्टी को मिलाया जाता है) और फिर राज्य की राजधानी में भेजा जाता है। राज्य स्तर से मिट्टी राष्ट्रीय राजधानी भेजी जाती है, जिसमें हजारों अमृत कलश यात्री भी होते हैं।

अमृत कलश यात्रा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ अपने कलश से मिट्टी एक विशाल अमृत कलश में डाली। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी, देश के हर हिस्से से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया जाएगा। ❑

स्रोत: पीआईबी

सत्यमेव जयते

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

विशेषताएं :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

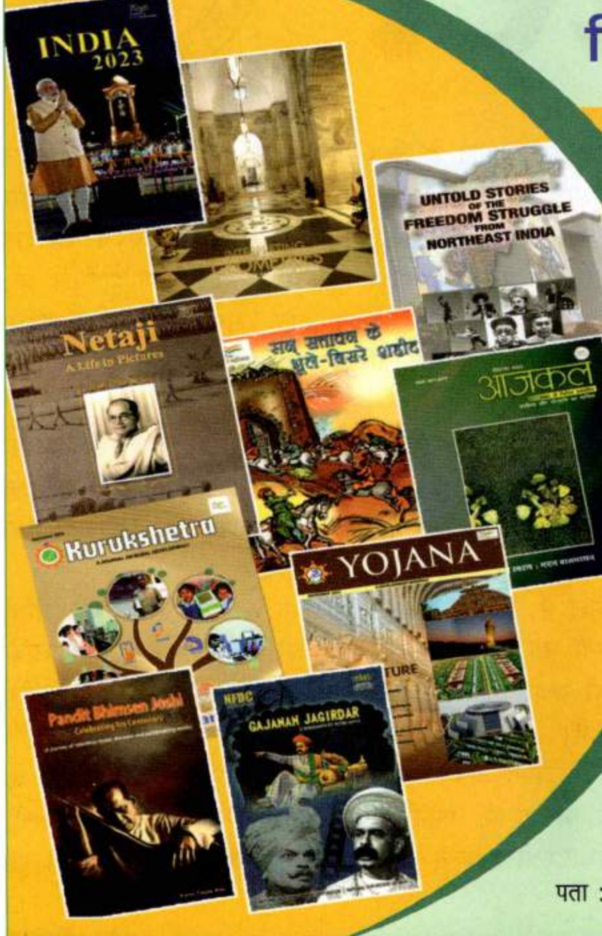

कृषि और ग्रामीण विकास
प्रमुख पहल और उपलब्धियां

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया था। मोटा अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ावा देने और भारत को इसके वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। सरकार ने इस वर्ष 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की सुविधा की घोषणा की है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि-बुनियादी ढांचे, जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां आदि स्थापित करना शामिल है।

डॉ जगदीप सक्सेना

पूर्व मुख्य संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

आत्मनिर्भर भारत की राह में ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, इस वर्ष, गांवों में समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बदलाव में तेजी लाने के लिए कई कार्यनीतिक कदम उठाए हैं। केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को लाभप्रदता, उत्पादकता और समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चल रही योजनाओं और नई पहलों के लिए 2023-24 के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,25,036 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 5 प्रतिशत अधिक है। सतत योजनाओं के लिए आवंटन के अलावा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि त्वरक कोष की स्थापना के लिए बजट प्रावधान किए गए थे। कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया और एक नई योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा' योजना शुरू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट में

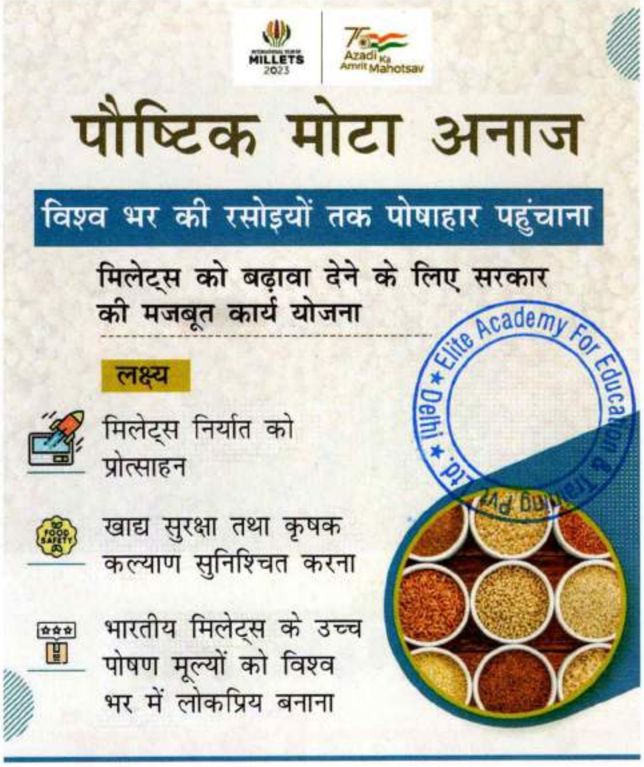

विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता और बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस (3 जुलाई 2023) को संबोधित करते हुए कहा, 'सरकार कृषि और किसानों पर औसतन सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है।' प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और देश को खाना पकाने के तेल में आत्मनिर्भर बनने में मदद करने का आह्वान किया। दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,59,964 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय का लक्ष्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के अलावा, विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकसित करना और देश में भूमि संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है। बजट में, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर) पर परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपये कर दिया गया। बजट में बड़े उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण की भी घोषणा की गई। उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल और सहायता प्रदान की जाएगी।

उच्च मानकों की स्थापना

भारत सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया था। मोटा अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ावा देने और भारत को मोटा अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। भारत ने, विशेष रूप से राष्ट्रीय संदर्भ में, सम्मान व्यक्त करने के लिए मोटा अनाज का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया। कई प्रचारात्मक और सहायक योजनाओं के कारण मोटा अनाज की घरेलू खपत बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति माह 14 किलोग्राम हो गई है, जो पहले 3 किलोग्राम से अधिक नहीं थी। हाल के दिनों में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी मांग बढ़ने के साथ मोटा अनाज आधारित खाद्य उत्पादों की बिक्री में भी लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। मोटा अनाज को और बढ़ावा देने तथा विस्तार के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के तहत देश के 19 जिलों को चुना गया है। 500 से अधिक स्टार्टअप और बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन अब सुपर मार्केट और मॉल में सीधी बिक्री के लिए मोटा अनाज आधारित विभिन्न पोषक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग में लगे हुए हैं। उसी तर्ज पर, महिला स्वयं सहायता समूह छोटे गांवों में मोटा अनाज उत्पाद तैयार कर रहे हैं और ये शहरी बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। मोटा अनाज मिशन ने मोटा अनाज की खेती में लगे लगभग 2.5 करोड़ किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्री अन्न की अपार संभावनाओं को सामने लाने के लिए नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस (मार्च 2023) का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक स्मारक टिकट और स्मारक सिक्के का अनावरण भी किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ-साथ 75 लाख से अधिक किसानों ने भी वर्चुअल मोड में भाग लिया।

खाद्य उत्पादन के मोर्चे पर, देश ने 2022-23 में क्रमशः 330 मिलियन टन और 352 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के साथ खाद्यान्न और बागवानी उपज दोनों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में 4 प्रतिशत (14 मिलियन टन) से अधिक की वृद्धि हुई, बागवानी उपज के उत्पादन में एक प्रतिशत (5 मिलियन टन) से अधिक की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में प्रमुख खाद्यान्न-धान (चावल), और गेहूं ने (जुलाई-जून चक्र) क्रमशः 135 मिलियन टन और 110 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च उत्पादन दर्ज किया। बागवानी फसलों में, फलों का उत्पादन 108 मिलियन टन रहा, और सब्जियों ने 213 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया।

उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप, सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। कुल मिलाकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। इसके बाद रेपसीड तथा सरसों (200 रुपये प्रति क्विंटल); गेहूं तथा कुसुम (रु.150/-क्विंटल); और जौ तथा चना (क्रमश: रु115 और रु.105/क्विंटल) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ, उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन अब गेहूं के लिए 102 प्रतिशत, रेपसीड तथा सरसों के लिए 98 प्रतिशत, मसूर के लिए 89 प्रतिशत, चना तथा जौ में प्रत्येक के लिए 60 प्रतिशत और कुसुम के लिए 52 प्रतिशत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में वृद्धि का पैटर्न खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और निर्भरता तथा आयात को कम करने के लिए तिलहन और दलहन के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे को दर्शाता है। इस बीच, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने सरकार को गेहूं और चावल के लिए अपनी ओपन-एंडेड खरीद नीति की गहन समीक्षा करने का सुझाव दिया है। पैनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वर्तमान नीति के कारण गेहूं और चावल के उच्च भंडार के संचय, विकृत फसल पैटर्न और भूजल के अत्यधिक दोहन पर प्रकाश डाला है। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता से अधिक गेहूं और चावल का भंडार है।

इसी सन्दर्भ में सरकार ने इस वर्ष 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की सुविधा की घोषणा की है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों

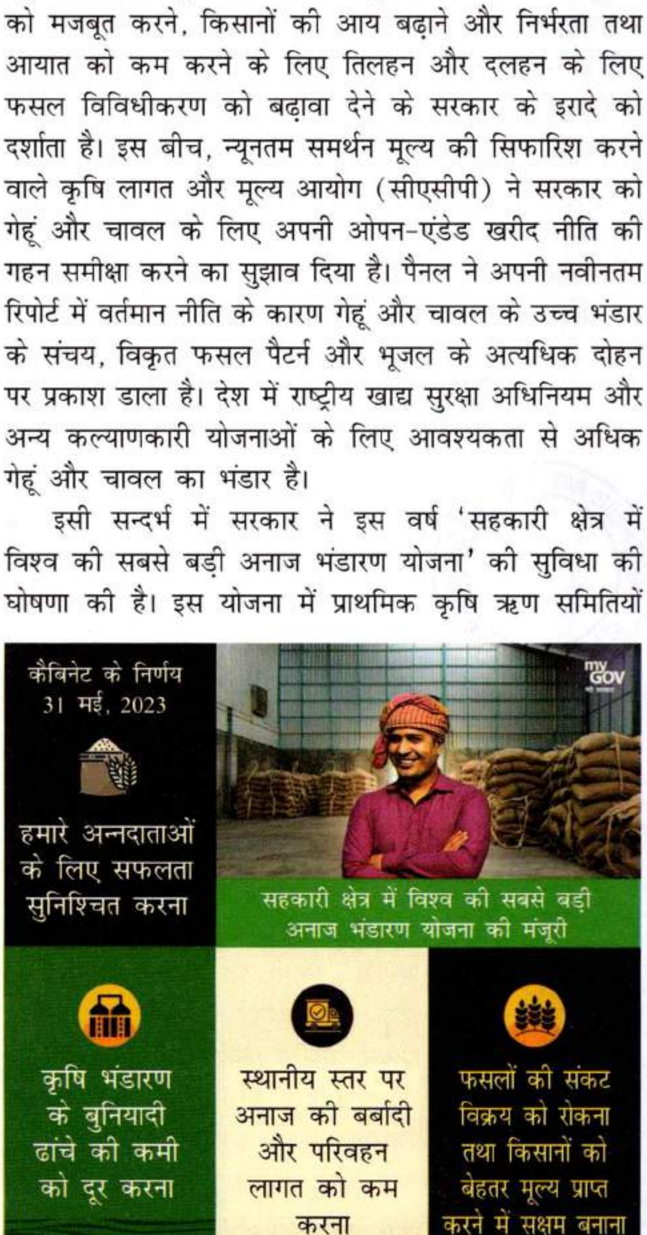

(पीएसीएस) के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि-बुनियादी ढांचे, जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां आदि की स्थापना शामिल है। एक लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 13 करोड़ से अधिक सदस्य किसानों के दूरगामी नेटवर्क के साथ, इस योजना में भोजन की बर्बादी में पर्याप्त कमी, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

विकास के लिए पहल

बजट प्रस्ताव (2023-24) के अनुसार, सरकार ने 'पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जेनरेशन, नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर-अर्थ' (पीएम-प्रणाम) योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य धरती मां के स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है। इसके अलावा, सरकार ने जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से गोबर्धन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित खाद के क्षेत्र में अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता को भी मंजूरी दी है। इस संदर्भ में, दुनिया में पहले तरल नैनो-डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) की शुरुआत (26 अप्रैल 2023) एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इफको (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड) द्वारा विकसित और उत्पादित, नैनो-डीएपी और नैनो-यूरिया (तरल) पेटेंट वाली वस्तुएं हैं जो कृषि क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। 2021 में नैनो-यूरिया के उत्पादन को मंजूरी दी गई और 2023 में देश में लगभग 17 करोड़ नैनो-यूरिया बोतलें बनाने का बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। मार्च 2023 तक लगभग 6.3 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जा चुका है। 500 मिलीलीटर की एक बोतल का फसल पर प्रभाव दानेदार यूरिया के 45 किलोग्राम बैग के बराबर होता है। तरल उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से उर्वरक आयात की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे देश के मूल्यवान राजस्व और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देगा। सरकार ने हाल ही में रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष, सरकार ने कुछ विशिष्ट आईटी-आधारित पहल शुरू कीं जिनका उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन में सुधार करना है। इनमें से पहली- किसान

क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है जिसे किसान ऋण पोर्टल कहा जाता है। इसे क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसानों को संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले कृषि ऋण का लाभ उठाने में भी सहायता करेगा। ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक 'घर घर केसीसी अभियान' नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। पोर्टल की कार्यक्षमता, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करने के लिए एक व्यापक विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम) मैनुअल लॉन्च किया गया था। विंड्स तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापकों का एक नेटवर्क स्थापित करने का एक प्रयास है। मौसम डेटा से फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन सुधार करने और जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष जी-20 की प्रतिष्ठित अध्यक्षता के दौरान, भारत ने हैदराबाद (15 से 17 जून, 2023) में जी-20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की। इसमें जी-20 देशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे भोजन तथा पोषण; जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि; समावेशी कृषि-मूल्यश्रृंखलाएं तथा खाद्य प्रणालियां और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटीकरण। बैठक के दो प्रमुख परिणाम हैं- (1) खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन हाई प्रिंसिपल 2023 और (2) अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल (महर्षि)। जी20 देशों ने सहायता और सहयोग प्रदान करके खाद्य सुरक्षा संकट से प्रभावित समुदायों की मुश्किलें तत्काल कम करने और लचीलापन बनाने का भी वादा किया।

ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि का मार्ग

सुरक्षा जाल बनाने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के विशिष्ट एजेंडे के साथ, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के केंद्र में ग्रामीण निवासी हैं जो आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में ग्रामीण विकास के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2024-30 के लिए एक मध्यम अवधि की योजना और 2024-47 के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष, अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की, 'आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको 'बैंक-वाली दीदी', 'आंगनवाड़ी दीदी', और 'दवाई-वाली दीदी' मिलेंगी। गांवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है।' इस परिकल्पना को साकार करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम, 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य दो करोड़ 'लखपति दीदियों - एसएचजी दीदियों' को सक्षम बनाना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित कर सकें। अभियान के दौरान, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह परिवार को मूल्यश्रृंखला में वृद्धि के साथ-साथ कई आजीविका गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 'संगठन से समृद्धि' किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना' 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत एक और राष्ट्रीय अभियान था, जिसका उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों से अतिरिक्त एक करोड़ महिलाओं को एसएचजी में

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

शामिल करना था। सभी राज्यों में आयोजित इस अभियान में उपायों, प्रेरणा, सुविधा और प्रशिक्षण के माध्यम से 1.1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के सफल समापन पर कुल 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह आंदोलन का हिस्सा होंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार समर्थन को मजबूत करने की दिशा में एक डिजिटल कदम के रूप में, 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ने एक अभिनव ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग उन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्राहक ई-सरस पोर्टल और ई-सरस मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं। यह ग्राहक के दरवाजे तक ऑनलाइन ऑर्डर लाने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को संभालेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखनऊ (यूपी) में 'अमृत महोत्सव' के तहत '50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना' अभियान शुरू किया है। यह 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा, जिसमें ग्रामीण महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 'बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या बीसी सखी' इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और गांवों में महिलाओं के सशक्तीकरण को गति दे रही है। बीसी सखियां ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बैंक नकदीकरण में भी मदद कर रही हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय शासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर ध्यान देने के साथ अपने 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (1.04.2023 से 31.3.2026) को नया रूप दिया है। इसके नौ विषयों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल-हितैषी, जल-पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासित और महिला-अनुकूल गांव शामिल हैं।

कल्याणकारी योजनाओं में, जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के कनेक्शन प्रदान करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। जीवन बदलने वाले इस मिशन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए, ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को शुरुआत (अगस्त 2019) के केवल 3.23 करोड़ घरों से बढ़ाकर केवल चार वर्षों में 13 करोड़ कर दिया है। 1 जनवरी, 2023 से हर दिन औसतन 87,500 नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस वर्ष, सरकार ने तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे कुल लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। उज्ज्वला के दूसरे चरण के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, लाभार्थियों को पहला रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों/कार्यक्रमों के तहत 7,45,780 कि.मी. लंबी 1,77,119 सड़कें बनाने में मदद की है। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विभिन्न आईटी तंत्रों को शामिल करने से अधिक पारदर्शिता के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तीकरण गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में तेजी आई है। रिकॉर्ड के अनुसार, इसने 2023-24 के दौरान 201.96 करोड़ व्यक्ति दिवस और 14.35 करोड़ सक्रिय कर्मचारियों के लिए रोजगार सृजन किया हैं। इस अवधि के दौरान, 5.04 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए और 33.5 करोड़ डीबीटी अंतरण दर्ज किए गए हैं। जल संरक्षण की दृष्टि से, मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य भविष्य के लिए देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। अब तक 67,000 से अधिक ऐसे सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 1.10 लाख से अधिक स्थलों की पहचान की गई है।

इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के नौ वर्ष पूरे हो गए हैं और 75 प्रतिशत से अधिक गांवों की ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) से मुक्ति इस संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन -ग्रामीण चरण - दो देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। राष्ट्र ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के दौरान 'कचरा-मुक्त भारत' थीम के साथ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाया। समुद्र तटों, नदी तटों, जल निकायों आदि की सफाई के अभियान में 109 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सरकार ने अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर अपना जोर जारी रखा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण, सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेशन तथा एकीकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका में बदलाव लाना है। ❑

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर समर्पित
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**" के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन" या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... **पत्रिका** .... **भाषा में भेजें।**

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... **ज़िला** .... **पिन** ....

ईमेल .... **मोबाइल नं.** ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... **दिनांक** .... **सदस्यता सं.** ....

प्रकाशन विभाग

परीक्षा तैयारी

के लिए

हमारा संग्रह

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

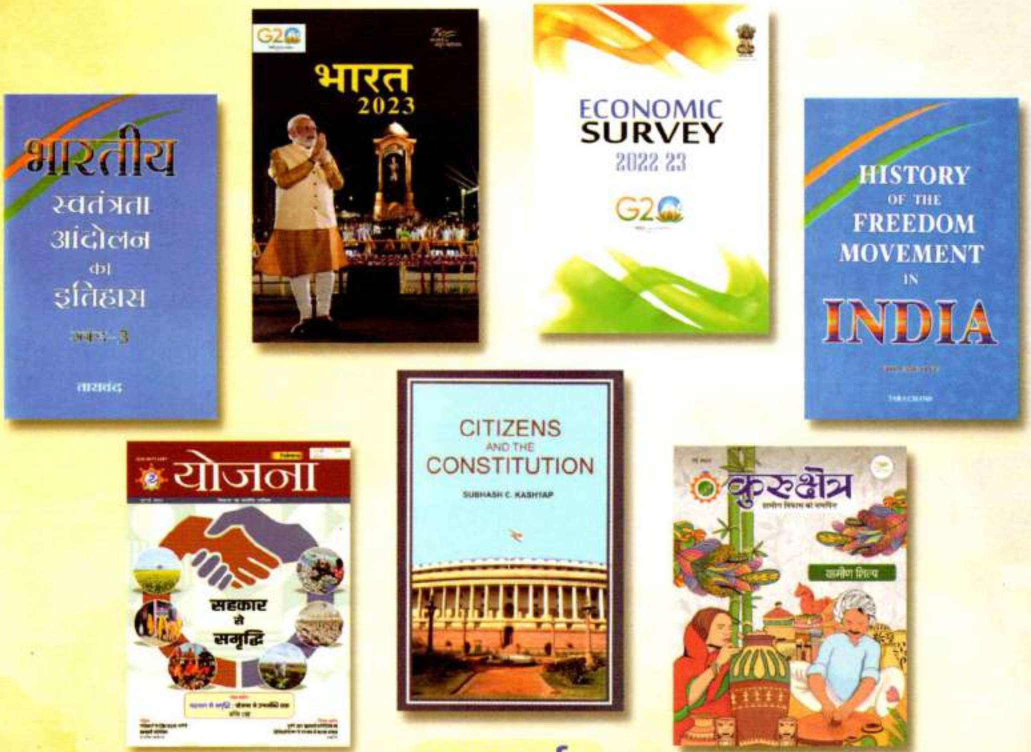

व अन्य कई...

रोज़गार संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण के लिए हर सप्ताह पढ़ें रोज़गार समाचार

सब्सक्राइब करें : www.employmentnews.gov.in

खरीदने के लिए : www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें:

पुस्तकों के लिए :	businesswng@gmail.com	01124365609
पत्रिकाओं के लिए:	pdjucir@gmail.com	01124367453

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003